भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस पेपर

भारत और लैटिन अमरीका संबंध

एसआईसीए का अभिज्ञान

डॉ. स्तुति बनर्जी और **डॉ. अर्णब चक्रवर्ती**

भारतीय वैश्विक
परिषद

भारत और लैटिन अमरीका संबंध

एसआईसीए का अभियान

डॉ. स्तुति बनर्जी और डॉ. अर्णब चक्रवर्ती

भारतीय वैश्विक
परिषद

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय वैश्विक परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। परिषद आज एक आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियाँ आयोजित करती है और प्रकाशन करती है। इसमें सुभंडारित पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और 'इंडिया क्वार्टरली' पत्रिका का प्रकाशन करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा दिया जा सके और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी है।

भारत और लैटिन अमरीका संबंध:
एसआईसीए का अभियान

प्रथम प्रकाशन मार्च 2023

© भारतीय वैश्विक परिषद

आईएसबीएन: 978-93-83445-75-2

सभी अधिकार सुरक्षित हैं। कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों का उत्तरदायित्व विशेष रूप से लेखकों का है और उनकी व्याख्या आवश्यक रूप से भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड
नई दिल्ली 110001, भारत

टेलीफोन: +91-11-2331 7242 | फैक्स: +91-11-2332 2710
www.icwa.in

विषय-वस्तु

सार.....5

1. प्रस्तावना.....7

2. सिस्तेमा डे ला इंटीग्रोसियन
सेंट्रोअमरीकाना (एसआईसीए) का विकास.....12

3. क्षेत्रीय शक्तियों के साथ एसआईसीए के संबंध.....24

4. हेमिस्फेरिक महाशक्ति के साथ एसआईसीए के संबंध:
संयुक्त राष्ट्र अमरीका.....28

5. क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति.....37

6. भारत-एसआईसीए संबंध: वर्तमान वास्तविकताएं और
भविष्य की दिशाएं.....51

7. निष्कर्ष.....66

सार

लैटिन अमरीका के अधिकांश देश अपने संबंधित इतिहास में लोकतंत्र की सबसे लंबी निर्बाध अवधि का अनुभव कर रहे हैं। इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को नए नेताओं के उदय, एक ध्रुवीकृत नागरिकों के साथ-साथ आर्थिक मंदी और बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानताओं और तेजी से बदलते अंतरराष्ट्रीय वातावरण की सामूहिक चुनौती का सामना करना पड़ा। लैटिन अमरीका में विकास का अपने पड़ोस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र अमरीका (यूएस) के साथ संबंध। पड़ोस से परे देखने में, ये देश न केवल व्यापार और आर्थिक साझेदारी बल्कि राजनयिक संबंधों में विविधता लाने के प्रयास में एशिया की ओर रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही चीन और भारत राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों के माध्यम से संबंधों को घनिष्ठ कर रहे हैं।

जैसा कि भारत ने इस क्षेत्र में पारंपरिक लैटिन अमरीकी भागीदारों से परे अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना शुरू कर दिया है; मध्य अमरीकी राज्यों की आर्थिक और सामरिक क्षमता ने भारतीय नीति निर्माताओं के बीच प्रमुखता प्राप्त की है। इस क्षेत्र के भीतर मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली (एसआईसीए) भारत के लिए मध्य अमरीका के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो उत्तर और दक्षिण अमरीका और दो महासागरों-अटलांटिक और प्रशांत के बीच सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पुल है। एसआईसीए की स्थापना 1991 में मध्य अमरीका में क्षेत्रीय एकीकरण के लिए पुनर्जीवित संस्थागत ढांचे के रूप में की गई थी। जैसा कि भारत और एसआईसीए दोनों राष्ट्र अपने संबंधों को सुदृढ़ करना चाहते हैं, यह अनिवार्य हो जाता है कि वे प्रत्येक की आवश्यकताओं के साथ-साथ अपनी-अपनी शक्तियों का पता लगाएं और सहयोग के उन क्षेत्रों की पहचान करें जो भविष्य में संबंधों को आगे बढ़ाएंगे।

संकेतशब्द: लैटिन अमरीका,एसआईसीए, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, संयुक्त राष्ट्र अमरीका, चीन, भारत

1. प्रस्तावना

लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र (एलएसी) क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों में पिछले कुछ दशकों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इस संबंध की शुरुआत 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मेक्सिको यात्रा से देखी जा सकती है, इसके बाद 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की क्षेत्र के आठ देशों की यात्रा हुई। हालांकि बीच के वर्षों में इस तरह की उच्च स्तरीय यात्राएं नहीं हुईं, लेकिन शीत युद्ध के दौरान और इसकी समाप्ति के बाद के दशकों में संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। 2014 में ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के साथ संबंधों को नया बल मिला। इस यात्रा ने 2018 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और 2016 और 2019 में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू की कई अन्य उच्च स्तरीय यात्राओं और 2018 में जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया है और सबसे हालिया दौरा अगस्त 2022 में हुआ था जब उन्होंने पराग्वे में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया था। डोमिनिकन गणराज्य, ग्वाटेमाला और पराग्वे जैसे भारतीय मिशनों का उद्घाटन राजनयिक संपर्क स्थापित करके और क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भारत के लिए देशों की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करके क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के भारत के प्रयास हैं।

भारत के लिए एलएसी का सामरिक महत्व

एलएसी क्षेत्र उभर रहा है और भारत के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में जिससे भारत-एलएसी संबंधों में तेजी आई है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं द्वारा दिखाए गए लचीलेपन ने एलएसी क्षेत्र को एक उभरते आर्थिक केंद्र के रूप में दिखाया। तब से इस क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और लोगों की ऊपर की ओर गतिशीलता और गरीबी में कमी के साथ स्थिर विकास देखा गया है। यह क्षेत्र आज पेरू, पैराग्वे आदि जैसी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं का स्थल है।

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका ने इस क्षेत्र के देशों के साथ जुड़ने की आवश्यकता को आवश्यक बना दिया है जो अपनी विदेश नीति में तेजी से सामरिक महत्व प्राप्त कर रहा है। यह जुड़ाव एलएसी देशों के बीच हाल ही में वैश्विक स्थिति और आर्थिक पुनर्गठन के साथ मेल खाता है। इस क्षेत्र के देश उत्तरी अमरीका और यूरोप में पारंपरिक भागीदारों से एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं तक व्यापार में विविधता लाने की तलाश कर रहे हैं। इसमें, भारत ने प्रमुखता प्राप्त की है क्योंकि यह इस क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो राजनीतिक रूप से स्थिर है और वैश्विक राजनीतिक वातावरण के आकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है जो

एलएसी देशों द्वारा निर्यात किए जाते हैं। एलएसी क्षेत्र में मीठे पानी, कृषि योग्य भूमि, खनिज और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। बदले में, भारत एलएसी सामानों के लिए एक विशाल बाजार उपलब्ध कराता है। निर्यात से परे, भारत एलएसी पर सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा और नवाचार आदि जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता भी प्रदान करता है। भारत और क्षेत्र के दोनों देश इस तथ्य को भी साझा करते हैं कि उनके पास युवा जनसांख्यिकी है जिसे लाभकारी रोजगार खोजने की आवश्यकता है। भारत भी क्षेत्र के सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करता है जो एक अतिरिक्त लाभ है। भारत और क्षेत्र के देशों ने ब्रिक्स, बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) और आईबीएसए (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) जैसे कई बहुपक्षीय रूपों में भागीदारी शुरू की है। भारत प्रशांत गठबंधन जैसे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तंत्र में एक भागीदार राष्ट्र है। भारत और क्षेत्र के देश संयुक्त राष्ट्र (यूएन), जी-20, जी-77 और जलवायु परिवर्तन वार्ता जैसे वैश्विक महत्व के संस्थानों में भी संलग्न हैं। इन वार्ताओं को हाल ही में वैश्विक शासन और सतत और न्यायसंगत विकास के क्षेत्रों में काफी गहरी बातचीत के साथ सीमित किया गया है।

ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक महत्व भी प्राप्त करता है। भारत अपनी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं का आयात करता है और व्यवधान देश के आर्थिक विकास को बाधित करते हैं। एलएसी क्षेत्र के देश ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हैं और भारत वहां ऊर्जा अन्वेषण परियोजनाओं में निवेश करके अपनी तेल कंपनियों के माध्यम से जुड़ना जारी रख सकता है। इसके अलावा एलएसी क्षेत्र दुनिया के सबसे स्वच्छ ऊर्जा बाजारों में से एक है। जैसा कि भारत हरित ऊर्जा पर जोर दे रहा है, यह भारत को इस क्षेत्र के देशों के साथ जुड़ने के लिए एक और स्थान प्रदान करता है। भारत जैव ईंधन के विकास के लिए ब्राजील के नेतृत्व वाले प्रयासों का हिस्सा है, बदले में, इस क्षेत्र के कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का हिस्सा हैं।

एलएसी क्षेत्र भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के विशाल क्षेत्र हैं और यह अपनी खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान के लिए भी जाना जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत और क्षेत्र के देश संयुक्त उद्यमों और अनुसंधान सहयोग के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं।

प्रारंभ में लगभग विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा नेतृत्व में, भारत और एलएसी क्षेत्र के बीच संबंध हाल के वर्षों में सरकारों के बीच अधिक संवाद और लोगों के बीच शुरुआती जुड़ाव के बाद से हैं। ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश 'इंडेंटेड' भारतीय श्रम को इस क्षेत्र में भेज दिया गया था, मुख्य रूप से कैरेबियन में औपनिवेशिक बागानों में काम करने के लिए। आज, भारतीय डायस्पोरा त्रिनिदाद, सूरीनाम और गुयाना की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। वर्तमान समय में, जबकि भारत से इस क्षेत्र में प्रवासियों का एक बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में मौजूद अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। भारतीय कंपनियां तेजी से एलएसी क्षेत्र की ओर देख रही हैं और इसमें लोगों की आवाजाही आवश्यक है। योग और आयुर्वेद को एलएसी में

कई अनुयायी मिले हैं। पर्यटन क्षेत्र में धीमी वृद्धि देखी जा रही है, विशेषकर उन लोगों के साथ जो साहसिक पर्यटक होंगे और जो नए गंतव्यों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

उपरोक्त सभी में भारत और क्षेत्र के देशों के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया ने अधिक महत्व प्राप्त किया है क्योंकि दुनिया चीन और अमरीका के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, यूक्रेन में चल रहे संकट में 'पश्चिम' बनाम रूस, महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी, गहराते दक्षिण-दक्षिण सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने की आवश्यकता के साथ एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सामना कर रही है। खाद्य और पोषण सुरक्षा, न्यायसंगत स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और जलवायु परिवर्तन से बढ़ती चुनौती को संबोधित करने की आवश्यकता। इन सभी में भारत पाता है कि वह एलएसी क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ पारस्परिक चिंताओं और समाधानों को साझा करता है।

जैसे-जैसे पारस्परिक अवसर उत्पन्न होते हैं, भारत और क्षेत्र के देशों को लाभकारी संबंधों को बढ़ाने और बनाने के लिए उनका लाभ उठाने की आवश्यकता है। ऐसा ही एक अवसर मध्य अमरीका के साथ विस्तारित जुड़ाव है। जैसा कि भारत ने इस क्षेत्र में पारंपरिक लैटिन अमरीकी भागीदारों से परे अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना शुरू कर दिया है; मध्य अमरीकी राज्यों की आर्थिक और सामरिक क्षमता ने भारतीय नीति निर्माताओं के बीच प्रमुखता प्राप्त की है[1]। इसका प्रमाण 2022 में विदेश राष्ट्र मंत्री मीनाक्षी लेखी की पनामा और होंडुरास की उच्च स्तरीय यात्राओं, विदेश राष्ट्र मंत्री श्री वी. मुरलीधरन की ग्वाटेमाला यात्रा और कोस्टा रिका और अल सल्वाडोर में सचिव (पूर्व) सुश्री रीवा गांगुली की अध्यक्षता में विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) के माध्यम से मध्य अमरीकी देशों के साथ भारत की बढ़ती वार्ता है। उच्च स्तरीय वार्ताओं की यह श्रृंखला भारत और मध्य अमरीका के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का परिणाम है जो व्यापार को और बढ़ाने की होड़ में हैं। मध्य अमरीका में कुल सात राष्ट्र हैं; बेलीज, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा। राष्ट्र भौगोलिक रूप से अपने लैटिन अमरीकी राष्ट्रों की तुलना में छोटे हैं और प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी प्रतिभाशाली नहीं हैं; हालाँकि, यह क्षेत्र उत्तर और दक्षिण अमरीका के बीच और दो महासागरों-अटलांटिक और प्रशांत के बीच पुल के रूप में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे-जैसे इस क्षेत्र के देश प्रमुखता प्राप्त करते हैं, उन्होंने ताकत को गठबंधन करने और एक दुर्जेय आर्थिक ब्लॉक बनने के प्रयास में सिस्तेमा डे ला इंटेग्रासियोन सेंट्रोअमरीकाना या सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम (एसआईसीए) का गठन किया है।

जैसे-जैसे पारस्परिक अवसर उत्पन्न होते हैं, भारत और क्षेत्र के देशों को लाभकारी संबंधों को बढ़ाने और बनाने के लिए उनका लाभ उठाने की आवश्यकता है।

मध्य अमरीका के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के लिए एसआईसीए महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह समूह महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि भारत रक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे सहयोग के उभरते क्षेत्रों में एसआईसीए देशों के साथ अपने संबंधों की पड़ताल करता है। सहयोग के प्रक्षेपवक्र ने सुधार के संकेत प्रदर्शित किए हैं लेकिन अभी भी कई मुद्दों को दूर करना बाकी है। रणनीतियों और नीतियों को एक-दूसरे की ताकत का लाभ उठाने और एक-दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए संगठन और मध्य अमरीकी क्षेत्रीय एकीकरण में इसकी भूमिका को समझना अनिवार्य है।

2. सिस्टेमा डी ला इंटीगेशियन सेंट्रोअमरीकाना (एसआईसीए) का विकास

2क एसआईसीए का विकास

1824 में कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला और निकारागुआ ने सेंट्रल अमेरिकन फेडरेशन का गठन किया। आंतरिक मुद्दों और गड़बड़ियों के कारण 1838 में संघ का पतन हो गया[2]। भले ही राजनीतिक और आर्थिक एकता हासिल करने से बहुत दूर थी, लेकिन इसने उन्हें आगे की कोशिश करने से नहीं रोका।

मध्य अमरीका के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के लिए एसआईसीए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए, यह माना जाता था कि क्षेत्रीय आर्थिक एकता की आवश्यकता होगी। इस तरह के उपायों से निवेश, उत्पादन और लेन-देन के लिए एक संपन्न क्षेत्र तैयार होगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 1950 के दशक में लैटिन अमरीका और कैरिबियन के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (ईएसएलएसी) ने मध्य अमरीका में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया। सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट (सीएसीएम)[3] का गठन 1960 में निकारागुआ, अल सल्वाडोर, होंडुरास और ग्वाटेमाला के प्रारंभिक सदस्यों के साथ किया गया था। कोस्टा रिका 1962 में संगठन में शामिल हो गया। प्रारंभ में यह टैरिफ में कमी और व्यापार को बढ़ावा देने के कारण अच्छी तरह से कार्य करता था, हालांकि, 1960 के दशक के अंत तक सदस्य राज्यों के बीच मतभेदों के कारण विभिन्न मुद्दे थे और सीएसीएम लड़खड़ा गया। मुख्य रूप से संस्थागत कमजोरी और आर्थिक लाभों के असमान वितरण के साथ पर्याप्त औद्योगिक आधार की अनुपस्थिति इसके पतन के मुख्य कारण थे।

टैरिफ में कमी के संबंध में सदस्य राज्यों के बीच बड़ी असहमति है। इसके अतिरिक्त, 1969 में होंडुरास और अल सल्वाडोर के बीच संघर्ष ने सीएसीएम के भीतर बड़ी असहमति पैदा की।

एसआईसीए की उत्पत्ति का पता ओडीईसीए (मध्य अमरीकी राज्यों का संगठन) और सीएसीएम से लगाया जा सकता है। ओडीईसीए ने एकीकरण के लिए मध्य अमरीकी उद्योगों के शासन और मुक्त व्यापार और मध्य अमरीकी एकीकरण की बहुपक्षीय संधि पर समझौते को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस पर वर्ष 1958 में हस्ताक्षर किए गए थे। शीत युद्ध के अंत और मर्कोसुर जैसे विभिन्न क्षेत्रीय एकीकरण मॉडल की शुरुआत के साथ, मध्य अमरीकी नेताओं ने अपने संबंधित क्षेत्र के लिए एक एकीकृत मॉडल पर जोर दिया। दिसंबर 1991 में मध्य अमरीकी देशों के राष्ट्रपतियों की ग्यारहवीं बैठक के ढांचे के भीतर टेगुसिगल्पा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने ओडीईसीए के चार्टर में संशोधन किया, जिससे एसआईसीए का निर्माण हुआ। एसआईसीए आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी 1993 को लागू हुआ।

इसके अलावा, मध्य अमरीकी आर्थिक एकीकरण की सामान्य संधि जिसे ग्वाटेमाला प्रोटोकॉल[4] के रूप में भी जाना जाता है, 29 अक्तूबर 1993 को हस्ताक्षरित किया गया था। इस संधि का उद्देश्य स्वेच्छा से और धीरे-धीरे मध्य अमरीका के भीतर एक आर्थिक संघ प्राप्त करना था। संधि ने ग्वाटेमाला में मध्य अमरीकी आर्थिक एकीकरण सचिवालय (एसआईईसीए) की भी स्थापना की। अगले कुछ वर्षों में, एसआईसीए को और सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न संधियों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि मध्य अमरीका के लिए सतत विकास के लिए गठबंधन (एएलआईडीईएस)[5] जिसे 1994 में लोकतंत्र, सामाजिक-सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद, मध्य अमरीकी सामाजिक एकीकरण पर संधि जिसे सैन सल्वाडोर की संधि के रूप में भी जाना जाता है, मार्च 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का उद्देश्य मध्य अमरीका में सामाजिक नीतियों के समन्वय, सामंजस्य और सुव्यवस्थितता को बढ़ावा देना था। अंत में, होंडुरास में दिसंबर 1995 में डेमोक्रेटिक सुरक्षा पर फ्रेमवर्क संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने मध्य अमरीकी डेमोक्रेटिक सुरक्षा मॉडल बनाया था। इसका उद्देश्य एसआईसीए के संस्थानों को सुदृढ़ करना, कानून का शासन सुनिश्चित करना है, और यह कि सरकारें सार्वभौमिक स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुप्त वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाती हैं।

वर्ष 2022 तक, एसआईसीए के सदस्य राष्ट्र कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा, बेलीज और डोमिनिकन रिपब्लिक हैं[6]।

एसआईसीए का केंद्रीय उद्देश्य मध्य अमरीका में एकीकरण को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसने कई सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो सदस्य राज्यों को अधिक क्षेत्रीय एकीकरण प्राप्त करने के उनके प्रयासों में मार्गदर्शन करते हैं। एसआईसीए के सिद्धांतों ने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को

सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय सुरक्षा विकसित करने और आर्थिक कल्याण और सामाजिक न्याय की प्रणाली के माध्यम से लोगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सदस्य देश सतत विकास की दिशा में भी काम करने के लिए समन्वय करेंगे। एसआईसीए का उद्देश्य सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने सदस्य राज्यों की उपस्थिति को बढ़ाना भी है। एक आर्थिक समूह के रूप में लक्षित, इसका उद्देश्य एक आर्थिक संघ के लक्ष्य को प्राप्त करना भी है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों में योगदान करने में सक्षम होगा। सदस्य राज्यों ने मध्य अमरीकी एकीकरण प्रणाली पर सहमति व्यक्त की जो शांति, विकास और स्वतंत्रता और लोकतंत्र की धारणा से निर्देशित होगी। अन्य सिद्धांतों के बीच सदस्य राज्यों ने भाग लेने या कोई भी कार्रवाई करने से बचने पर सहमति व्यक्त की जो एसआईसीए के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है और कानूनी और शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से सभी विवादों को हल करने के लिए।

एसआईसीए का केंद्रीय उद्देश्य मध्य अमरीका में एकीकरण को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसने कई सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो सदस्य राज्यों को अधिक क्षेत्रीय एकीकरण प्राप्त करने के उनके प्रयासों में मार्गदर्शन करते हैं।

चित्र एक: एसआईसीए सदस्य राष्ट्र

स्त्रोत: https://www.gn-sec.net/sites/default/files/event/files/8_ryan_cobb_sicreee_presentation.pdf

मध्य अमरीका में क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, एसआईसीए ने स्थापित किया कि सदस्य राज्यों के अध्यक्ष सभी मध्य अमरीकी देशों के सामान्य हितों में से एक होंगे जो बाद में एसआईसीए में व्याप्त थे, शांति की स्थापना, हिंसा की अस्वीकृति, लोकतंत्रीकरण और लोकतांत्रिक लोकाचार का अभ्यास था।

मध्य अमरीका में क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, एसआईसीए ने स्थापित किया कि सदस्य राज्यों के अध्यक्ष प्रत्येक छह माह में मिलेंगे। उन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा उनके काम करने में मदद की जाएगी। एसआईसीए कार्यकारी समिति और सामान्य सचिवालय को संगठन के दिन-प्रतिदिन का कामकाज सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, एसआईसीए में उपाध्यक्षों, मध्य अमरीकी संसद (पीएआरएलएसीईएन), सेंट्रल अमेरिकन कोर्ट ऑफ जस्टिस (सीसीजी) और सलाहकार समिति (सीसी-एसआईसीए)[7] की बैठक भी है।

2 ख सदस्य देशों के हितों का अभिसरण

जबकि सीएसीएम की स्थापना से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 1960 में केवल 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 1970 में 26 प्रतिशत हो गई[8], फिर भी सीएसीएम के पतन ने सुनिश्चित किया कि विकास को बनाए नहीं रखा जा सका। 1987 में एस्किपुलस समझौते[9] के बाद ही इस क्षेत्र में शांति लौट आई और क्षेत्रीय एकीकरण को फिर से बढ़ावा दिया जा सका।

सभी मध्य अमरीकी देशों के सामान्य हितों में से एक जो बाद में एसआईसीए में व्याप्त हो गया, शांति की स्थापना, हिंसा की अस्वीकृति, लोकतंत्रीकरण और लोकतांत्रिक लोकाचार का अभ्यास था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तीन प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये थे; 1987 का एस्क्विपुलस समझौता, 1988 की अलाजुएला घोषणा[10] और 1989 में मध्य अमरीकी राष्ट्रपतियों की संयुक्त घोषणा[11]। इन समझौतों ने राष्ट्रों को क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक योजना तैयार करने, सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रक्रिया में तेजी लाने का अवसर प्रदान किया। इसने मध्य अमरीकी संसद या पीएआरसीएएलईएन के निर्माण का नेतृत्व किया। एसआईसीए के तत्वावधान में पार्कलेन ने एकीकरण की सुविधा के लिए तेरह अलग-अलग आयोगों की भी स्थापना की।

एसआईसीए के सदस्य देशों के पारस्परिक हित हैं और निम्नलिखित मुद्दों के समान विचार हैं।

(क.) आर्थिक एकीकरण प्राप्त करना अभिसरण का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। एसआईसीए की स्थापना व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने के लिए की गई थी, जिससे कॉफी और चीनी जैसे कुछ उत्पादों पर कुछ अपवादों के साथ क्षेत्र के भीतर श्रम और पूंजी और निवेश की गतिशीलता की अनुमति मिलती है। सदस्य देश ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे उत्पादों पर देश-विशिष्ट टैरिफ नहीं लगाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से यह भी सहमति व्यक्त की है कि जो सामान पूरी तरह से मध्य अमरीका में उत्पन्न हुए थे, उन्हें मुक्त व्यापार उपचार प्राप्त होगा। एक सामान्य बाहरी टैरिफ[12] भी अपनाया गया था जो मध्य अमरीका में उत्पन्न नहीं होने वाले सामानों पर शुल्क लगाता है। जलवायु परिवर्तन और इससे उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता ने इस समृद्ध जैव-विविध क्षेत्र के देशों को भी एक साथ लाया है। पर्यावरण और विकास पर केंद्रीय अमरीकी आयोग (सीसीएडी)[13] के तहत पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए सभी सदस्य राज्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए एक रोडमैप बनाया गया है। इसमें वनों के संरक्षण, कम कार्बन उन्मुख कृषि और पशुधन प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के प्रयास शामिल हैं। यह टिकाऊ कृषि के लिए और एक विस्तारित निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रणाली विकसित करने पर जोर देता है। 2030 तक एसआईसीए का उद्देश्य दस मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल और संरक्षित करना और 204014 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है[14]। एसआईसीए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य देशों और संस्थानों के साथ भी काम कर रहा है। यह मेसोअमेरिकन रीफ सिस्टम के लिए बेसिन-टू-रीफ दृष्टिकोण के साथ ट्रांस-बाउंड्री एकीकृत प्रबंधन परियोजना पर वैश्विक पर्यावरण (जीईएफ)[15] के लिए फंड के साथ सहयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एसआईसीए एक ग्रीन क्लाइमेट बैकग्राउंड इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ, सीएबीईआई और जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ भी सहयोग कर रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय समुदायों में लचीलापन पैदा होगा। सामाजिक समानता अभिसरण का एक और क्षेत्र है। सेंट्रल अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी फॉर सोशल डेवलपमेंट (ओसीएडीईएस)[16] एसआईसीए के भीतर एक उपप्रणाली है जो सामाजिक सुरक्षा और समानता, पोषण और भोजन तक पहुंच जैसी प्रमुख सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करना चाहती है। इसके भीतर खाद्य और पोषण सुरक्षा पर क्षेत्रीय वेधशाला (ओबीएसएएन-आर)[17] 2009 में स्थापित की गई थी, जो इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करती है। एसआईसीए में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा (आईएनसीएपी) भी है[18], जो खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है।

(ख.) प्रवासन एक और विषय है जिस पर कुछ हद तक आम सहमति हासिल की गई है। प्रोयेक्टो

अल्टरनैटिव्स[19] मध्य अमरीकी सामाजिक एकीकरण सचिवालय (एसआईएससीए) द्वारा किए गए एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और होंडुरास जैसे सदस्य राज्यों में प्रवासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है। इसके अतिरिक्त, फ्री मोबिलिटी पर मध्य अमरीकी समझौता (सीए-4)[20] एक नीति है जिसके तहत अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास ने प्रवासन प्रक्रिया को मानकीकृत करने के प्रयास में यात्रा को आसान बना दिया है।

(ग.) स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा और उन्हें सफलता प्राप्त करने में मदद करना एसआईसीए सदस्य राज्यों का एक लक्ष्य रहा है जिसे वे सीआईसीए (सेंट्रल अमेरिकन इंडिजिनस काउंसिल)[21] के माध्यम से प्राप्त करने की आशा करते हैं, जो स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, एक अंतर-सांस्कृतिक विकास दृष्टिकोण की तर्ज पर शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना चाहता है।

(घ.) लोकतांत्रिक सुरक्षा एक और विषय है जहां एसआईसीए के सदस्य राष्ट्र समान हितों को साझा करते हैं। एसआईसीए के दायरे में, लोकतांत्रिक सुरक्षा का अर्थ है नागरिक समाज को सुदृढ़ करना, नागरिकों के लिए सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गतिविधियों ने इस क्षेत्र को आईसीआरआईएमई[22] (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए मध्य अमरीका में आपराधिक स्तर में सहयोग) के माध्यम से अपने प्रयासों को समन्वित करने की मांग करने वाले देशों के साथ त्रस्त कर दिया है, संगठन उन अपराधों से निपटता है जो तेजी से अभियोजन और न्याय प्रदान करना सुनिश्चित करते हैं। मध्य अमरीकी सुरक्षा रणनीति[23] को 2011 में एसआईसीए के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था जो सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना, कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करना और नागरिकों के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना चाहता है।

(ई.) एसआईसीए राष्ट्र भी महामारी से लड़ने के अपने प्रयासों में एकजुट हुए। मध्य अमरीकी सामाजिक एकीकरण परिषद की 73$^{वीं}$ साधारण बैठक की पृष्ठभूमि में, एसआईसीए क्षेत्रीय एकीकरण सामाजिक नीति (पीएसआईआर-एसआईसीए)[24] 2020-2024 को मंजूरी दी गई थी। पीएसआईआर-एसआईसीए सदस्य देशों के बीच आम मुद्दों और हितों पर ध्यान केंद्रित करने की नीति है, जो महामारी के बाद के प्रभावों से निपटने में समाधान खोजने के लिए उनके बीच सहयोग का आह्वान करता है। यह बहुआयामी सामाजिक नीति उस सामान्य दृष्टि का उत्पाद है जो सभी सदस्य राष्ट्र साझा करते हैं। यह समाज में असमानता और संरचनात्मक समस्याओं को कम करने, पोषण और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को किफायती बनाने

और स्वास्थ्य सेवा पर भी केंद्रित है।

जैसा कि ध्यान दिया जा सकता है कि एसआईसीए सदस्य राष्ट्र कई मुद्दों पर एकजुट होते हैं, फिर भी, उनके बीच मतभेद बने हुए हैं जिन्हें समूह के कामकाज के समग्र परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझने की भी आवश्यकता है।

2 ग सदस्य देशों के बीच मतभेद

एसआईसीए का सभी सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण है। हालांकि, क्षेत्रीय एकीकरण से संबंधित सभी मामलों पर एकजुटता को बढ़ावा देना मुश्किल है।

यह देखा गया है कि सदस्य राज्यों के बीच राजनीतिक एकता प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक गतिशीलता, शासन और नियम हैं जो कई बार बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं।

यह देखा गया है कि सदस्य राज्यों के बीच राजनीतिक एकता प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक गतिशीलता, शासन और नियम हैं जो कई बार बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। सदस्य देशों के बीच अनसुलझे सीमा विवाद भी एसआईसीए के कामकाज में बाधा साबित हुए हैं। निकारागुआ और कोस्टा रिका[25], ग्वाटेमाला और बेलीज, होंडुरास और अल सल्वाडोर[26] के बीच विवादों ने एकीकरण प्रक्रिया को प्रभावित किया है। ये उदाहरण और मुद्दे क्षेत्रीय एकता को बाधित करते हैं। उदाहरण के लिए, पीएआरएलएसीईएन या मध्य अमरीकी संसद क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है लेकिन कोस्टा रिका और बेलीज अभी तक इसका हिस्सा नहीं हैं। क्षेत्रीय स्तर पर निर्णय लेना कठिन हो जाता है। राज्यों के भीतर संरचनात्मक कमजोरियों के कारण समझौतों का कार्यान्वयन एसआईसीए के लिए एक बाधा रहा है।

राष्ट्रीय संस्थानों की कमजोरी क्षेत्रीय संस्थागत कमजोरी में बदल जाती है। देशों में अलग-अलग राष्ट्रीय प्राथमिकताएं भी हैं जो एसआईसीए के कामकाज को प्रभावित करती हैं। यह स्पष्ट हो गया क्योंकि देश प्रवासन, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल आदि के मुद्दों को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, 2015 में कोस्टा रिका क्यूबा प्रवासन संकट पर अपनी असहमति के कारण एसआईसीए शिखर सम्मेलन[27] से अस्थायी रूप से हट गया, जब क्यूबा के प्रवासी निकारागुआ के माध्यम से मार्ग अधिकारों से इनकार करने के बाद कोस्टा रिका में फंस गए थे।

भ्रष्टाचार एक और मुद्दा है जो क्षेत्रीय एकीकरण को बाधित करता है। एसआईसीए द्वारा भ्रष्टाचार और इसके उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए एक आम आधार और सामंजस्य ढूंढना वास्तव में मुश्किल है। इसलिए समझौतों का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। आर्थिक विवाद किसी भी क्षेत्रीय संगठन के भीतर होते हैं और एसआईसीए कोई अपवाद नहीं है। कई विवाद ज्यादातर टैरिफ और फाइटोसैनिटरी और ज़ूसैनिटरी स्थितियों से संबंधित हैं जो एसआईसीए के दायरे में हुए हैं। इनमें से अधिकांश मामले कृषि उत्पादों, मध्यवर्ती वस्तुओं, गोजातीय और अन्य मांस, डेयरी उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात और आयात से संबंधित हैं। इनमें से अधिकांश मामलों पर निर्णय विभिन्न अधिकरणों द्वारा दिए गए थे जबकि कुछ का पारस्परिक रूप से निपटान किया गया था[28]। इसके मतभेदों से अवगत एसआईसीए उन्हें संबोधित करने के लिए प्रयास कर रहा है और यह प्रगति पर है।

3. क्षेत्रीय शक्तियों के साथ एसआईसीए के संबंध

ब्राज़ील

ब्राजील 7 अक्तूबर 2008 को एसआईसीए में एक पर्यवेक्षक बन गया[29]। अल सल्वाडोर में कई विचार-विमर्श के बाद, दक्षिण अमरीकी राष्ट्र ने ब्राजील के पूर्व विदेश मंत्री सेल्सो अमोरिम और एसआईसीए के पूर्व महासचिव एनीबल क्विनोनेज के नेतृत्व में एसआईसीए के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एक पर्यवेक्षक देश के रूप में, यह वोट के अधिकार के बिना एसआईसीए की कार्यवाही में भाग लेता है। एसआईसीए और ब्राजील दोनों के लिए, साझेदारी पारस्परिक रूप से लाभप्रद रही है, ब्राजील विशेष रूप से जैव-ईंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपने व्यापार में विविधता लाने के विकल्पों की खोज कर रहा है और एसआईसीए सदस्य राज्यों को ब्राजील के बाजार तक पहुंच प्राप्त करना एक फायदा रहा है। भविष्य को देखते हुए, दोनों पक्ष आर्थिक और तकनीकी सहयोग को गहरा करने, व्यापार संबंधों को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन और सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों के व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए सहयोग करने के लिए काम कर रहे हैं।

कोलंबिया

कोलंबिया एसआईसीए के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है और 26 सितंबर 2013 को अपनी पर्यवेक्षक स्थिति को औपचारिक रूप दिया[30]। कोलंबिया के पूर्व विदेश मंत्री मारिया एंजेल होल्गुइन और एसआईसीए के पूर्व महासचिव ह्यूगो मार्टिनेज ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में कोलंबिया का प्रवेश क्षेत्र के सुरक्षा आयामों को देखते हुए महत्वपूर्ण था। कोलंबिया-पनामा सीमा को प्रवासन के साथ-साथ

नशीली दवाओं की तस्करी के लिए विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है जो इस क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा चिंता का विषय है। कोलंबिया इस तरह की सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन में एसआईसीए के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है।

एसआईसीए सदस्य राज्यों के सुरक्षा कर्मी अपने कोलंबियाई समकक्षों के साथ नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिसके अलावा खुफिया जानकारी साझा करने के लिए तंत्र हैं। मध्य अमरीकी सुरक्षा रणनीति के दायरे में एक भागीदारी वाला देश होने के नाते[31], कोलंबिया हिंसा की रोकथाम के उपायों, आतंकवाद विरोधी और मादक पदार्थों का मुकाबला करने जैसी कई चुनौतियों को संबोधित करने के लिए सदस्य राज्यों के साथ रणनीतितैयार करने में योगदान देता है।
एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भागीदार होने के अलावा, कोलंबिया एसआईसीए का एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार भी है। एसआईसीए और एंडियन नेशंस समुदाय (सीएएन)[32], जिसका कोलंबिया एक सदस्य है, दोनों पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता तक पहुंच सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करते हैं। हाल ही में, लोकतांत्रिक उपायों के कार्यान्वयन, मानवाधिकारों और कानून के शासन को संबोधित करने के संबंध में एसआईसीए और कैन के बीच कई दौर की चर्चा हुई है। जलवायु परिवर्तन एक और क्षेत्र है जिस पर सहयोग के बारे में विचार-विमर्श हुआ है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति पनामा, निकारागुआ और होंडुरास जैसे कुछ देशों की भेद्यता को देखते हुए। महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर खामियों को उजागर किया और परिणामस्वरूप इन चुनौतियों से निपटने के लिए संगठनों में संस्थानों को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।

मेक्सिको

मेक्सिको 11 नवंबर 2004 को एसआईसीए में भीतर एक पर्यवेक्षक बन गया। मेक्सिको एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है और एसआईसीए के साथ इसकी साझेदारी एसआईसीए की पहुंच को व्यापक बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम था। मेक्सिको ने 1990 के दशक की शुरुआत में कॉन्सर्टेशन मैकेनिज्म और टक्सटला डायलॉग के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति-निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति होने के नाते 2013 में एसआईसीए और मैक्सिको के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते[33] को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम था। मेक्सिको-एसआईसीए सहयोग पिछले एक दशक से प्रौद्योगिकी, जलवायु निगरानी, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों और क्षेत्रों पर व्यापक हो गया है। जलवायु सेवाओं के लिए मेसोअमेरिकन सेंटर की स्थापना जलवायु परिवर्तन की निगरानी और कमजोरियों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक अकादमिक आदान-प्रदान कार्यक्रम जिसे एएनयूआईईएस-सीएसयूसीए (नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, मेक्सिको-सेंट्रल अमेरिकन हायर यूनिवर्सिटी काउंसिल) के रूप में जाना जाता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग में सहायता करता है।

इनके अलावा मेक्सिको मेसोअमरीका प्रोजेक्ट[34] पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिसके द्वारा यह बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सार्वजनिक संस्थानों और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर भागीदारी करता है। उदाहरण के लिए, मेक्सिको एसआईसीए देशों के बीच मेक्सिको को विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने परिवहन के लिए अपनी भू-संदर्भित सूचना प्रणाली के माध्यम से एसआईसीए देशों में परिवहन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में भी सक्षम बनाया है। इसने मेसोअमेरिकन पब्लिक हेल्थ सिस्टम और मेसोअमरीका हंगर फ्री प्रोग्राम जैसे अन्य कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इसके अलावा मध्य अमरीकी पब्लिक स्कूलों के लिए समर्थन पर सहयोग और एसआईसीए के उत्तरी त्रिकोण देशों से अकेले बच्चों के प्रवास से संबंधित चिंताओं को संबोधित करना उल्लेखनीय है।

4. हेमिस्फेरिक महाशक्ति के साथ एसआईसीए के संबंध: संयुक्त राष्ट्र अमरीका

4क क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की भागीदारी का इतिहास

एक क्षेत्रीय महाशक्ति होने के नाते, संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने हमेशा मध्य अमरीका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र में इसकी उपस्थिति का पता 1823[35] के मोनरो सिद्धांत में लगाया जा सकता है जिसने मैनिफेस्ट डेस्टिनी की अवधारणा को प्रतिष्ठापित किया।

1900 के दशक की शुरुआत के दौरान अमरीकी नीति निर्माता अभी भी आश्वस्त थे कि पूरे महाद्वीप में विदेशी हस्तक्षेप की तलाश रखना संयुक्त राष्ट्र अमरीका की जिम्मेदारी थी। 1907 में वाशिंगटन सम्मेलन[36] ने इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र अमरीका के लिए एक अग्रणी भूमिका सुनिश्चित की। 1923 में, संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा प्रायोजित, शांति और मैत्री[37] की सामान्य संधि इस क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने और तख्तापलट जैसे अवैध साधनों के माध्यम से सत्ता संभालने वाली किसी भी सरकार की मान्यता को रद्द करने के लिए तैयार की गई थी। यह क्षेत्र में प्रभाव डालने का एक और प्रयास था।

एक क्षेत्रीय महाशक्ति होने के नाते, संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने हमेशा मध्य अमरीका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

जैसे-जैसे अमरीकी उपस्थिति के साथ-साथ इस क्षेत्र में इसका निवेश भी बढ़ा, रूजवेल्ट प्रशासन द्वारा यह महसूस किया गया कि गोलार्ध को इन घटनाओं से अलग रखने की आवश्यकता थी और 1933 में सातवें पैन-

अमेरिकन सम्मेलन में 'अच्छे पड़ोसी नीति' की घोषणा की[38]। इस नीति के अनुसार, पैन-अमेरिकीवाद की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया गया था जहां पूरे गोलार्ध को विदेशी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और एक दूसरे के लिए रैली करनी चाहिए। मध्य और लैटिन अमरीका में हस्तक्षेप करने के बजाय, विचार एक अनुकूल वातावरण बनाना था जहां बाकी देश वाशिंगटन के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करेंगे।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र अमरीका कई देशों के वामपंथियों की ओर मुड़ने से चिंतित हो गया और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लैटिन अमरीका सोवियत संघ की पहुंच से बाहर रहे। इस प्रकार मध्य अमरीका शीत युद्ध के दौरान प्रॉक्सी यूएस-सोवियत संघर्ष के थिएटर में बदल गया। इस क्षेत्र में अपनी प्राथमिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने आर्थिक सहायता, निवेश की नीति का पालन किया, जबकि कई अवसरों पर सैन्य हस्तक्षेप में भी संलग्न था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र अमरीका कई देशों के वामपंथियों की ओर मुड़ने से चिंतित हो गया और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लैटिन अमरीका सोवियत संघ की पहुंच से बाहर रहे।

मध्य अमरीका में संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक 1954 में ग्वाटेमाला में हुआ[39], जब सीआईए (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी) प्रायोजित तख्तापलट में राष्ट्रपति जैकोबो अर्बेन्ज़ की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। विचारधारा और अमरीकी आर्थिक हितों की रक्षा को तख्तापलट के पीछे तर्क के रूप में उद्धृत किया गया था। पनामा के साथ, पनामा नहर पर नियंत्रण और संप्रभुता के सवाल के बारे में मुद्दे थे। 1958 में, कैनाल 40 पर अमरीकी ध्वज के साथ पनामा ध्वज को फहराने की अनुमति देने की मांग की गई थी[40], जिससे अमरीकी बलों और नागरिकों के बीच झड़पें हुईं। राष्ट्रपति आइजनहावर ने स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों के झंडे फहराने का निर्देश दिया। इसी तरह की घटनाएं 1964[41] में भी हुईं, जिसके कारण फिर से झड़पें हुईं और व्यवस्था बहाल करने के लिए बल प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति कैनेडी के प्रशासन के दौरान, एलायंस फॉर प्रोग्रेस[42] लॉन्च किया गया था। यह सोवियत संघ के प्रभाव का मुकाबला करने और लैटिन अमरीकी राज्यों के बीच प्रभाव हासिल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी वित्तीय सहायता कार्यक्रम था। 1965 में डोमिनिकन गणराज्य, 1966 में ग्वाटेमाला, 1981 में अल सल्वाडोर, 1981 में निकारागुआ और 1982 में होंडुरास में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सेनाओं द्वारा सैन्य हस्तक्षेप भी किए गए थे।

शीत युद्ध की समाप्ति के साथ, संयुक्त राष्ट्र अमरीका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और मध्य

अमरीका के प्रति उसका दृष्टिकोण कुछ परिवर्तनों से गुजरा। इसने महसूस किया कि विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बहुत कम हो गया है। क्षेत्रीय रूप से, दशकों के संघर्ष के बाद शांति मध्य अमरीका में क्षेत्र के भीतर लोकतंत्र की ओर क्रमिक संक्रमण के साथ शुरू हुई।

लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, मध्य अमरीका के साथ संयुक्त राष्ट्र अमरीका के संबंधों में अधिक सहयोग देखा गया। सोवियत संघ के अब खंडित होने के साथ, संयुक्त राष्ट्र अमरीका अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है और मध्य अमरीका वाशिंगटन से न्यूनतम हस्तक्षेप का सामना करने वाली अपनी नीतियों को तैयार कर सकता है।

जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश की अध्यक्षता के दौरान, मध्य अमरीका निकारागुआ, कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला में चुनावों के साथ सुलह और शांति के रास्ते पर था। अल सल्वाडोर ने गृह युद्ध का सामना करना जारी रखा, और बुश प्रशासन युद्धरत समूहों के बीच शांति समझौते को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा था। इस अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमरीका की नीति लोकतंत्रीकरण, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना था जिससे संघर्ष समाप्त हो गया। आर्थिक मोर्चे पर एंटरप्राइज ऑफ द अमरीकाज़ इनिशिएटिव[43] को गोलार्ध में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और कुछ देशों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि, यह वह अवधि भी थी जब बुश प्रशासन ने पनामा पर आक्रमण का आदेश दिया, जिसे अमरीका के साथ संबंध रखने वाले मैनुअल नोरिएगा को हटाने के लिए ऑपरेशन जस्ट कॉज[44] के रूप में कोडनाम दिया गया था। यह मध्य अमरीका में अंतिम सैन्य हस्तक्षेप था।

मध्य अमरीका की ओर राष्ट्रपति क्लिंटन का ध्यान प्रकृति में महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अवधि के दौरान मध्य अमरीका से प्रवासन और नशीली दवाओं की तस्करी प्रमुख हो गई थी। 1994 में अमरीका[45] का पहला शिखर सम्मेलन मियामी में आयोजित किया गया था जहां पूरे अमरीका को शामिल करते हुए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए एक दृष्टि प्रस्तावित की गई थी। अपने पूर्ववर्ती की तरह, राष्ट्रपति क्लिंटन पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और सोमालिया में संघर्षों में व्यस्त थे। हालांकि, उन्होंने मध्य अमरीका की ओर आगे बढ़े जब उन्होंने होंडुरास और निकारागुआ के लिए आर्थिक सहायता और स्थगित भुगतान की पेशकश के माध्यम से ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ और होंडुरास का दौरा किया। मध्य अमरीका से प्रवासन सबसे प्रमुख मुद्दा था जिसका सामना राष्ट्रपति क्लिंटन को करना पड़ा था, इसके प्रत्युत्तर में निकारागुआ और मध्य अमरीकी समायोजन अधिनियम[46] को 1997 में लागू किया गया था जिसने इस क्षेत्र के प्रवासियों को कुछ राहत प्रदान की थी।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में क्लिंटन के उत्तराधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मध्य अमरीका के उत्तरी त्रिकोण में प्रवासन और आर्थिक परेशानियों और इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति से निपटना पड़ा। राष्ट्रपति बुश ने एक अर्धगोलाकार मुक्त व्यापार के विचारों पर ध्यान

केंद्रित किया जिसमें वह मध्य अमरीका को शामिल करना चाहते थे। लोकतांत्रिक लोकाचार को लागू करना और संस्थानों को सुदृढ़ करना अमरीकी प्रशासन के लिए एक और चुनौती थी और 2001 में इंटर-अमेरिकन डेमोक्रेटिक चार्टर[47] को अपनाया गया था। अमरीकी प्रशासन ने महसूस किया कि चीन का मुकाबला करने और मध्य अमरीका से आप्रवासन को रोकने के लिए, विशेष रूप से उत्तरी त्रिकोण से, आर्थिक नीतियों को क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना होगा। इस संबंध में मध्य अमरीका समृद्धि परियोजना[48] को गरीबी और प्रवासन के पीछे मूल कारणों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। बुश प्रशासन ने बाद में 2004 में संयुक्त राष्ट्र अमरीका, मध्य अमरीकी देशों और डोमिनिकन गणराज्य को शामिल करते हुए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र[49] बनाया। 9/11 हमलों और उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध ने अमरीकी प्रशासन का ध्यान मध्य अमरीका से हटा दिया, जिससे चीन जैसी अन्य शक्तियों को अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान मिला।

जबकि बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमरीका और मध्य अमरीकी राज्यों के बीच प्रवासन, नशीली दवाओं की तस्करी और सुरक्षा से संबंधित समस्याएं प्रमुख चिंता का विषय थीं। मुख्य उपलब्धियों में से एक मध्य अमरीकी क्षेत्रीय सुरक्षा पहल[50] की नींव थी जिसने अपराध और तस्करी का मुकाबला करने के लिए मध्य अमरीकी राज्यों को आर्थिक और सुरक्षा सहायता दी। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और इन देशों में कानून प्रवर्तन में सुधार करने में मदद करना था। मध्य अमरीकी नागरिक सुरक्षा साझेदारी और पश्चिमी गोलार्ध काउंटर ड्रग रणनीति[51] को इस क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया था। प्रवासी संकट के अलावा राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के दौरान, अमरीका में घुसपैठ करने वाले आपराधिक गिरोहों का मुद्दा एक बड़ी समस्या बन गई। दोनों पक्षों के प्रयासों के बावजूद, अमरीका में प्रवेश पाने वाले प्रवासियों की संख्या पर प्रतिस्पर्धा थी।

डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका और मध्य अमरीका के बीच संबंधों में कुछ मुद्दों को देखा। राष्ट्रपति ट्रम्प इस क्षेत्र से प्रवासन को रोकने के लिए बहुत उत्सुक थे और उन्होंने अमरीका-मेक्सिको सीमा के साथ एक अवरोध[52] का निर्माण किया। प्रवासियों की लहर के बारे में चिंतित, ट्रम्प प्रशासन ने ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर के साथ चर्चा की और प्रवासियों के प्रवाह को धीमा करने के लिए समझौतों[53] पर आया, जिससे उन्हें तीसरे देश में रहने के विकल्प मिले, जबकि उनके दावों को संसाधित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में आप्रवासियों को रोकने के लिए मेक्सिको[5455] में बने रहने के रूप में जानी जाने वाली एक नीति भी लागू की गई थी। जबकि आप्रवासन से संबंधित मुद्दे परिभाषित[56] हो गए, ट्रम्प प्रशासन को मध्य अमरीका में चीन की बढ़ती उपस्थिति से भी जूझना पड़ा।

जबकि राष्ट्रपति बिडेन का प्रशासन क्षेत्र में पारंपरिक मुद्दों का सामना कर रहा है, चीन की उपस्थिति द्वारा प्रमुख चुनौती प्रदान की जा रही है। बीजिंग इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नायक बन गया है, और व्यापार और निवेश के मामले में यह अमरीका के साथ प्रतिस्पर्धा में है। चीन ने 2007 के बाद से

आकर्षक निवेश की पेशकश करके, बुनियादी ढांचे में सहायता करके और उन्हें ताइवान से दूर करके मध्य अमरीका के साथ अपने जुड़ाव को लगातार बढ़ाया है। चीन ने महामारी से निपटने के लिए इन देशों को चिकित्सा सहायता और सहायता प्रदान करके सद्भावना भी प्राप्त की। वर्तमान अमरीकी प्रशासन को नई नीतियों के माध्यम से इस क्षेत्र के साथ फिर से जुड़ना होगा।

वर्तमान अमरीकी प्रशासन ने निकारागुआ, होंडुरास और अल सल्वाडोर के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए ट्रम्प प्रशासन की कई नीतियों को रद्द करके इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं।

अब तक बाइडन प्रशासन की चार वर्षों की अवधि में इस क्षेत्र में 4 बिलियन अमरीकी डॉलर[57] का निवेश करने की योजना है। खाद्य सुरक्षा को एक प्रमुख चिंता के रूप में उद्धृत करते हुए, विशेष रूप से उत्तरी त्रिकोण देशों में यूएसएआईडी[58] के माध्यम से 331 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई गई है। निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में और अधिक निवेश के लिए आमंत्रित करने पर चर्चा हो रही है और अब तक 750 मिलियन अमरीकी डॉलर[59] का निवेश किया जा चुका है, जबकि 1.9 बिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2022 में लॉस एंजिल्स में आयोजित अमरीका के नौवें शिखर सम्मेलन में, उपयोगी चर्चा हुई और बिडेन प्रशासन ने क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए जलवायु परिवर्तन, आवास, स्वच्छ ऊर्जा, लोकतांत्रिक शासन और महामारी और इसके प्रभावों से लड़ने पर योजनाओं की घोषणा की।

मुख्य ध्यान गोलार्ध के सभी देशों की साझा जिम्मेदारी पर था। पलायन एक प्रमुख मुद्दा है जो विमर्श पर हावी है और कुछ कदम उठाए गए हैं। 2021 में महामारी के कारण स्थिति विशेष रूप से जटिल थी, इसलिए बाइडन प्रशासन ने प्रवासन को धीमा करने और महामारी से लड़ने के लिए इन देशों को वित्त पोषित करने के लिए 2022[61] में 252 मिलियन अमरीकी डॉलर[60] और 861 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया। विचार इन देशों को लचीला बनाना है ताकि लोगों के पास संयुक्त राष्ट्र अमरीका में प्रवास करने का कोई कारण न हो। फरवरी 2021 में, प्रवासन को सुव्यवस्थित करने के लिए कार्यकारी आदेश 14010[62] पारित किया गया था, और उसी माह में अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास के साथ प्रवासन पर ट्रम्प युग 2019 के समझौतों को निलंबित कर दिया गया था। मार्च 2021 में सेंट्रल अमेरिकन माइनर्स प्रोग्राम[63] की पुनर्स्थापना देखी गई, जो फंसे हुए परिवारों को पुनर्मिलन की अनुमति देता है, और कुछ एमपीपी मामलों को जल्दी से संसाधित किया जा रहा था। अल्पकालिक लक्ष्यों की तलाश करने के बजाय, क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सहायता कार्यक्रमों जैसी दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जुलाई 2021 में, प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए अमरीकी रणनीति के रूप में जानी जाने वाली एक नीति शुरू की गई थी और अमरीका के नौवें शिखर सम्मेलन में प्रवासन और संरक्षण[64] पर लॉस एंजिल्स घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे।

जबकि संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने महसूस किया है कि एसआईसीए देशों को संलग्न करने के लिए कई दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, चीन की बढ़ती उपस्थिति इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने भविष्य के संबंधों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।

जबकि संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने महसूस किया है कि एसआईसीए देशों को शामिल करने के लिए कई दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, चीन की बढ़ती उपस्थिति इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने भविष्य के संबंधों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।

5. क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति

5क क्षेत्र में चीन के हितों के विकास का पता लगाना

शीत युद्ध के दौरान, चीन ने क्यूबा के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा क्योंकि यह 1959 की क्रांति 65 के बाद राजनयिक रूप से अलग-थलग था[65]। इस युग के दौरान, लैटिन अमरीका के संपर्क में आने के मामले में विकल्प बीजिंग के लिए सीमित हो गए। इसके पास इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र अमरीका को चुनौती देने के लिए संसाधन या साधन नहीं थे।

1970 और 1980 के दशक के अंत तक प्रमुख लैटिन अमरीकी देशों के साथ संबंध स्थापित किए गए थे, जिन्होंने लैटिन अमरीका और चीन को तीसरी दुनिया के सदस्यों के रूप में चित्रित किया था, संप्रभुता, आर्थिक स्वतंत्रता और दो महाशक्तियों के विरोध में। हालांकि, मध्य अमरीका के प्रति बीजिंग की पहुंच मुख्य रूप से दो कारकों के कारण सीमित रही-पहला, एक बहुत सुदृढ़ अमरीकी उपस्थिति और दूसरा, यह क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल की सबसे खराब अवधि का सामना कर रहा था।

मध्य अमरीका के प्रति बीजिंग की पहुंच मुख्य रूप से दो कारकों के कारण सीमित रही-पहला, एक बहुत सुदृढ़ अमरीकी उपस्थिति और दूसरा, यह क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के अपने सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा था।

शीत युद्ध का अंत एक और महत्वपूर्ण घटना थी जिसने लैटिन अमरीकी राष्ट्रों को पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध स्थापित करने के लिए अन्य देशों से संपर्क करने के लिए कुछ जगह दी, और चीनियों ने इस अवसर का

लाभ उठाया।

उस दशक में, चीन ने रियो समूह[66] में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1994 में लैटिन अमरीकी एकीकरण संघ (एलएआईए) का एक पर्यवेक्षक राष्ट्र बन गया, जिसके बाद 1997 में कैरेबियन विकास बैंक की सदस्यता हुई। दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तरीय दौरे हुए, जिसने धीरे-धीरे संबंधों को सुदृढ़ किया। 2001 में राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लैटिन अमरीका[67] में छह देशों का दौरा किया। 2002 में बीजिंग विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और लैटिन अमरीका के साथ व्यापार संबंध तेज हो गए। शीत युद्ध के दौरान, लैटिन अमरीका के प्रति चीन के दृष्टिकोण को सुदृढ़ वैचारिक रंग के साथ बदल दिया गया था[68], केवल शीत युद्ध के बाद की अवधि में व्यावहारिकता, आर्थिक और राजनयिक आवश्यकताओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मध्य अमरीका में चीन की रुचि मुख्य रूप से आर्थिक और सामरिक कारणों से थी। 2004 और 2008 में राष्ट्रपति हू जिंताओ ने लैटिन अमरीकी देशों की यात्राएं कीं जो काफी सार्थक थीं[69]।

2008 में, चीन ने अपनी पहली व्यापक लैटिन अमरीकी नीति जारी की जिसे 2016 में अपडेट किया गया था[70]। इन नीतियों ने सहयोग के क्षेत्रों का संकेत दिया और उच्च प्राथमिकता के तेरह क्षेत्रों की पहचान की जैसे व्यापार और वाणिज्य से संबंधित चैंबरों और संस्थानों के बीच सहयोग, उच्च मूल्य वर्धित वस्तुओं में निवेश, औद्योगिक और कृषि निवेश और विनिर्माण में सहयोग। राष्ट्रपति जिनपिंग ने महत्वाकांक्षी रूप से 1+3+6 सहयोग योजना की घोषणा की, जहां प्राथमिक ध्यान सीईएलएसी (लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय) के साथ साझेदारी है[71]। उन्होंने क्षेत्र के साथ चीन के संबंधों में तीन प्रेरक शक्तियों-वित्तीय सहयोग, व्यापार और निवेश की पहचान की और सहयोग ऊर्जा, तकनीकी नवाचार, वैज्ञानिक सहयोग, संसाधन, विनिर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के छह प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की।

आठ एसआईसीए सदस्य देशों में से, चीन कोस्टा रिका, पनामा, अल सल्वाडोर, डोमिनिकन गणराज्य और निकारागुआ के साथ राजनयिक संबंध रखता है।

भले ही चीन ने लैटिन अमरीका में अपना दृष्टिकोण काफी देर से शुरू किया, लेकिन यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नायक बन गया है। इसने अमरीका के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की है, जिसने हमेशा इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाया है। एसआईसीए के सदस्य देशों के प्रति चीन का दृष्टिकोण वाशिंगटन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

5ख एसआईसीए सदस्य राज्यों और चीन के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति

आठ एसआईसीए सदस्य देशों में से, चीन के कोस्टा रिका, पनामा, अल सल्वाडोर, डोमिनिकन गणराज्य, निकारागुआ और होंडुरास के साथ राजनयिक संबंध है। बेलीज और ग्वाटेमाला के साथ इसके राजनयिक संबंध नहीं हैं, हालांकि आर्थिक संबंध मौजूद हैं। कोस्टा रिका पहला काउंटी था जिसने 2007 में इसे मान्यता दी और इसके साथ संबंधों को सुदृढ़ किया। इसके बाद 2017 में पनामा का स्थान रहा। अल सल्वाडोर और डोमिनिकन गणराज्य ने जल्दी से इसका अनुसरण किया और 2018 में उन्होंने इसे मान्यता दी। 2021 में निकारागुआ ने चीन के साथ राजनयिक संबंधों को भी सुदृढ़ किया। 2023 में, होंडुरास ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।

यह क्षेत्र में आर्थिक और सामरिक लाभ देखता है, विशेष रूप से पनामा नहर के संबंध में जो अक्सर व्यापार के लिए चीनी जहाजों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्र में बीआरआई (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) को आगे बढ़ाने में भी रुचि रखता है। बीजिंग भी उस क्षेत्र में खुद को मजबूती से स्थापित करना चाहता है जो अमरीका के करीब है।

कोस्टा रिका 1 जून 2007 को चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला एसआईसीए देश था[72]। बदले में, बीजिंग ने कोस्टा रिकान ऋण में 300 मिलियन अमरीकी डॉलर खरीदे और सैन जुआन में एक खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर आवंटित किए। दो निगरानी विमानों के साथ कोस्टा रिकान पुलिस अकादमी को एक नई इमारत दान की गई थी। इसने कोस्टा रिका विश्वविद्यालय में कन्फ्यूशियस संस्थान की स्थापना भी की[73]। अगस्त 2007 में, कोस्टा रिका के राष्ट्रपति ऑस्कर एरियस ने सहायक विदेश मंत्री हे याफेई के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। अक्तूबर 2007 में राष्ट्रपति एरियस ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने के लिए बीजिंग की यात्रा की। चीनी पक्ष ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 27 मिलियन अमरीकी डॉलर के अलावा बाढ़ राहत के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की पेशकश की। कोस्टा रिका की राष्ट्रीय तेल रिफाइनरी (आरईसीओपीई) और चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम (सीएनपीसी) के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के विचार पर चर्चा हुई। नवंबर 2008 में राष्ट्रपति हू जिंताओ ने कोस्टा का दौरा किया। रिका और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, वित्त, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित ग्यारह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की घोषणा की। 2010 में कोस्टा रिका-चीन एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 2011 में लागू हुआ था[74]। 2012 में राष्ट्रपति लौरा चिंचिला ने चीन का दौरा किया और 2013 में राष्ट्रपति जिनपिंग ने सैन जोस की यात्रा की[75]। 2015 में राष्ट्रपति लुइस गुइलेर्मो सोलिस और विदेश मंत्री मैनुअल गोंजालेस ने बीजिंग का दौरा किया। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। 2020 में कोस्टा रिका को चीनी निर्यात 1.97 बिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि कोस्टा रिका लगभग 287 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात करता है[76]। ट्रांसमिशन उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे उत्पाद चीन के मुख्य निर्यात हैं जबकि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण, कॉफी, फल और अन्य कृषि उत्पाद कोस्टा रिकान निर्यात का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। हालांकि कोस्टा रिका को महामारी के मद्देनजर बीजिंग से चिकित्सा सहायता मिली, लेकिन इसने सिनोवैक कोविड वैक्सीन को इसकी कम प्रभावकारिता का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया[77]। वर्ष 2022 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के पंद्रह साल

का समारोह आयोजित किया, और लैटिन अमरीकी मामलों पर चीन के विशेष प्रतिनिधि, किउ ज़ियाओकी ने इस अवसर को चिह्नित करने के लिए सैन जोस का दौरा किया।

पनामा अपने सामरिक स्थान के कारण सबसे महत्वपूर्ण एसआईसीए देशों में से एक है। चीन का मुख्य निवेश लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में है। 1999 में चीनी फर्म हचिसन-व्हाम्पोआ को पनामा नहर में बंदरगाह निर्माण के लिए रियायतें मिलीं। पनामा कोलोन कंटेनर पोर्ट (पीसीसीपी) के रूप में जाना जाने वाला एक नए कंटेनर बंदरगाह के लिए चीनी लैंडब्रिज कंसोर्टियम द्वारा 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया गया था[78] । पनामा 2017 में बीआरआई में शामिल हुआ और 19 एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। 2018 में राष्ट्रपति जिंगपिंग ने पनामा का दौरा किया और अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण और खनन में भी महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। चीनी खनन कंपनी जियांग्शी की कोबरे पनामा माइन में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है[79]। पनामा सिटी से डेविड तक 5.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश के लिए एक हाई-स्पीड रेल लिंक का निर्माण करने की योजना थी, लेकिन परियोजना में देरी हुई और अंततः रुक गई। सैन मिगुएलिटो में एक डिजिटल मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए 38 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया गया है[80]। दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है, जहां हुआवेई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तपोषण बैंक ऑफ चाइना द्वारा किया जाता है जो चीन को दी गई राजनयिक मान्यता से पहले भी मौजूद था और जून 2020 में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2020 में पनामा ने चीन को 405 मिलियन अमरीकी डॉलर के सामान का निर्यात किया और बदले में 8.8 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात किया[81]। चीन को पनामा का मुख्य निर्यात तांबा अयस्क, खाद्य उत्पाद जैसे आटा, गोजातीय मांस और क्रस्टेशियन हैं। पनामा इसके साथ व्यापार में लगातार वृद्धि बनाए रखता है। चीन मशीनरी, जहाजों, नौका नौकाओं और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है।

चीन सांस्कृतिक कूटनीति को प्रोत्साहित करता है और पनामा विश्वविद्यालय में एक कन्फ्यूशियस संस्थान मौजूद है, चीन में अध्ययन करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। चीन ने पनामा के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा है, 2019 में चीनी विदेश मंत्री ने पनामा के पूर्व विदेश मंत्री एलेजांद्रो फेरर के साथ सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की और 2022 में वर्तमान विदेश मंत्री एरिका मोयनेस के साथ भी यही दोहराया गया[82]। महामारी के दौरान, चीन अपनी चिकित्सा सहायता के साथ उदार था, भले ही पनामा ने चीनी टीकों के उपयोग से इनकार कर दिया। जबकि पिछले वरेला प्रशासन ने सुदृढ़ आउटरीच की, वर्तमान कोर्टिज़ो प्रशासन ने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के लिए अधिक जांच-परख दृष्टिकोण अपनाया है।

चीन ने मई 2018 में डोमिनिकन गणराज्य के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद राष्ट्रपति डेनिलो मदीना ने नवंबर 2018 में बीजिंग की यात्रा की। दोनों देशों के बीच अठारह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और विभिन्न वाणिज्यिक परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए एक मिश्रित आयोग बनाया गया। संबंधों की स्थापना पर तुरंत 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की घोषणा की गई और आगे 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया गया[83]। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीनी दूतावास का उद्घाटन करने के लिए सितंबर

2018 में डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा की, जहां उन्होंने 'एक चीन' सिद्धांत को बनाए रखने के लिए मेजबानों को धन्यवाद दिया और अधिक सहयोग का वादा किया। बुनियादी ढांचे और रसद में निवेश, लोगों के बीच संपर्क और उच्च स्तरीय यात्राओं के बारे में घोषणाएं की गईं। डोमिनिकन गणराज्य ने बीआरआई का हिस्सा बनने और यूएनएससी, सीईएलएसी, पूर्वी एशिया-लैटिन अमरीका मंच और चीन के मंच जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। राष्ट्रपति मदीना ने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नवंबर 2018 में बीजिंग का दौरा किया। 90 मिलियन अमरीकी डॉलर की 14 परियोजनाओं की घोषणा की गई थी जो ज्यादातर निर्माण और रसद से संबंधित थीं। बीजिंग ने बिजली के बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने और मंज़ानिलो बंदरगाह में निर्माण के लिए 600 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण की भी पेशकश की, जबकि डोमिनिकन रम, तंबाकू और अन्य कृषि उत्पादों के आयात में वृद्धि का वादा किया। झोंगिंग लिंघम, एक चीनी खनन कंपनी इस क्षेत्र में काम करती है और वित्तपोषण के संदर्भ में बैंक ऑफ चाइना ऐसी परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करता है[84]। वर्तमान राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर के तहत, चीन के साथ संबंध सुदृढ़ बने रहे, भले ही बंदरगाहों और दूरसंचार[85] जैसे सामरिक क्षेत्रों में चीनी निवेश को शुरू में रोक दिया गया था, जो संभावित सीमित जुड़ाव का संकेत देता था। हालांकि, महामारी के दौरान टीकों और चिकित्सा आपूर्ति के दान ने बीजिंग को सद्भावना अर्जित करने की अनुमति दी। द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है जो 2020 में 442 बिलियन अमरीकी डॉलर है[86]। देश में काम कर रही चीनी कंपनियां केवल छह से बढ़कर पच्चीस हो गईं। मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हुई थी लेकिन अब तक यह मूर्त रूप नहीं ले सका है। चीन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है और चीनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कन्फ्यूशियस संस्थान चलाता है।

अल सल्वाडोर ने अगस्त 2018 में सल्वाडोर सांचेज सेरेन की अध्यक्षता में चीन को मान्यता दी थी। सद्भावना के संकेत के रूप में बीजिंग ने 3000 टन चावल भेजा और तेरह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन अमरीकी डॉलर मंजूर किए[87]। राष्ट्रपति नायब बुकेले की चुनावी जीत ने शुरू में एक धारणा दी कि नए स्थापित संबंधों को संदेह के घेरे में रखा जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति बुकेले ने अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2019 में बीजिंग की यात्रा की। बीजिंग ने विशेष रूप से निर्माण और रसद से संबंधित क्षेत्रों में अधिक निवेश का वादा किया और बड़ी मात्रा में कॉफी, फल और अन्य कृषि उत्पादों को खरीदने में रुचि व्यक्त की। अल सल्वाडोर ने बीआरआई में रुचि व्यक्त की और कहा कि यह 'एक चीन' सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करेगा। बीजिंग ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर और जल उपचार सुविधा के लिए 85 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रस्ताव दिया। इसने सर्फ सिटी परियोजना के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का भी वादा किया[88]। एशिया-प्रशांत जुआनहाओ द्वारा विकसित किए जाने वाले एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए भी रुचि व्यक्त की गई। चीनी निवेश हुआवेई और जेडटीई जैसी कंपनियों के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में भी मौजूद हैं और सल्वाडोर के टेलीविजन नेटवर्क टीवीएक्स बीआरआई मीडिया समुदाय में शामिल हो गए। दोनों देशों के बीच व्यापार वर्ष 2002 में 61 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 474 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। वर्तमान में, अल सल्वाडोर ने 2020 में 170 मिलियन अमरीकी डॉलर के सामान का निर्यात किया, जबकि चीन ने उसी वर्ष 1.36 बिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात किया[89]। अल सल्वाडोर ज्यादातर विद्युत कैपेसिटर, कपड़े, वस्त्र, गन्ना चीनी और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। दूसरी ओर चीन इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसमिशन उपकरण और मशीनरी जैसे तैयार उत्पादों का निर्यात करता है। अल सल्वाडोर को पांच बैचों में सिनोवैक टीकों की आपूर्ति की गई, इसके अलावा चिकित्सा उपकरण और

परीक्षण किट भी दिए गए।

निकारागुआ ने 09 दिसंबर 2021[90] को चीन के पक्ष में राजनयिक संबंधों को बदल दिया और ऐसा करके एक समान पैटर्न का पालन करते हुए एक और एसआईसीए सदस्य राष्ट्र बन गया। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि शुरू में इसने ताइवान को मान्यता दी थी; 1985 में इसने चीन को मान्यता दे दी। 1990 में इसने फिर से ताइवान में संबंध बदल दिए जो 2021 तक जारी रहे। यह मान्यता संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन के समय मिली। एक संयुक्त बयान में विदेश मंत्री वांग यी ने निकारागुआ के महामारी राहत कार्यों और महत्वपूर्ण पहलुओं पर सहयोग के लिए समर्थन व्यक्त किया और यहां तक कि मनागुआ को बीआरआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसने एक संभावित एफटीए पर भी चर्चा की और कन्फ्यूशियस संस्थान खोलने पर विचार किया। जनवरी 2022 में, राष्ट्रपति जिंगपिंग के विशेष दूत काओ जियानमिंग ने निकारागुआ की यात्रा की और कई विचार-विमर्श के बाद चार सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए[91]। **पहला बीआरआई में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करने वाले निकारागुआ से संबंधित था, जबकि दूसरे ने दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित किया था।**

क्षेत्र के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती गैर-औद्योगिकरण की समस्या बनी हुई है।

तीसरा मुद्दा वीजा छूट के बारे में था और अंतिम एक राजनीतिक परामर्श तंत्र स्थापित करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन था। अन्य एसआईसीए सदस्य देशों की तुलना में दोनों देशों के बीच व्यापार मामूली है। 2020 में चीन ने 727 मिलियन अमरीकी डॉलर के सामान का निर्यात किया, जिसमें ज्यादातर कपड़े, रसायन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और मोटरबाइक शामिल थे। बदले में, निकारागुआ ने 13.1 मिलियन अमरीकी डॉलर के सामानों का निर्यात किया जिसमें वनस्पति तेल, लकड़ी और कॉफी शामिल थे[92], हालांकि देर से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है।

लैटिन अमरीका में चीन और डीइंडस्ट्रियलाइजेशन

इस क्षेत्र के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती गैर-औद्योगिकरण की समस्या बनी हुई है। लैटिन अमरीका और चीन के बीच व्यापार 2000 में मामूली यूएस $ 12 बिलियन से बढ़कर 2020 में यूएस $ 300 बिलियन हो गया है[93]। चीन ऋण के साथ भी उदार रहा है और क्षेत्र में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश किया है। बहरहाल, इन निवेशों और ऋणों के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।

यह देखा गया है कि चीनी हित प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो लैटिन अमरीका में प्रचुर मात्रा में हैं और इस क्षेत्र से कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में हैं। एक छोटी अवधि में, प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात लैटिन अमरीकी देशों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रवाह में योगदान देता है। ऐसी विशेषताओं का नकारात्मक प्रभाव चीनी बाजार पर इन देशों की निर्भरता है[94]। चीन में हालिया आर्थिक मंदी को देखते हुए, इसका प्रभाव पूरे लैटिन अमरीका में भी पड़ा है, जहां वस्तुओं का धीमा निर्यात देखा गया है। एक अन्य पहलू जिसका बड़े पैमाने पर अध्ययन नहीं किया गया है, वह लैटिन अमरीका में आर्थिक गतिविधियों का *'चीनीकरण'* है, जहां परियोजनाओं को ज्यादातर न्यूनतम स्थानीय भागीदारी के साथ चीनी द्वारा पूरी तरह से निपटाया जाता है।

निर्यात के लिए चीनी बाजार पर यह निर्भरता कई कारकों के कारण है, उनमें से प्रमुख चीन की तुलना में स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए उच्च मांग उत्पन्न करने में असमर्थता, निर्यात की स्थिरता (महामारी के बाद की अवधि में चीनी अर्थव्यवस्था के धीमे होने तक) है जो विदेशी मुद्रा के निरंतर प्रवाह और बुनियादी ढांचे के निर्माण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए चीनियों की क्षमता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, चीन अपनी राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक संरचनाओं के बावजूद सरकारों के साथ जुड़ने का इच्छुक है और इसके समझौते बिना किसी शर्त के हैं।

इस अत्यधिक निर्भरता ने लैटिन अमरीकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी चुनौतियां पैदा की हैं। उदाहरण के लिए, कच्ची वस्तुओं की कीमत रिटर्न निर्धारित करती है और कीमतों में गिरावट के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं[95], उदाहरण के लिए कम मांग के साथ-साथ सोया की कम कीमत जो ज्यादातर अर्जेंटीना और ब्राजील द्वारा निर्यात की जाती है, ने इस वस्तु पर कम रिटर्न के कारण उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, इन देशों की औद्योगिक गतिविधि में कमी देखी गई है, क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं चीन को आउटसोर्स की जाती हैं, जो उन्हें पूरा करने के लिए अपनी श्रम शक्ति लाती हैं। किसी भी देश के लिए, न्यूनतम निर्भरता के साथ अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की क्षमता एक अतिरिक्त लाभ है, जो इस क्षेत्र में काफी हद तक गायब है[96]। इसलिए निष्कर्ष निकालने के लिए, इस क्षेत्र में चीन की आर्थिक गतिविधियां कौशल-विकास में योगदान नहीं करती हैं और इन देशों को निर्यात अभिविन्यास की ओर क्षमता निर्माण में निवेश करने से दूर करती हैं जो फिर से चीन के घरेलू बाजार पर निर्भर है। इन कारकों से भविष्य में परिणामों के साथ क्षेत्र में धीरे-धीरे औद्योगिकीकरण हो सकता है। लैटिन अमरीका और चीन के बीच व्यापार 2000 में 12 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 300 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। चीन ऋण के साथ भी उदार रहा है और विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस क्षेत्र में बहुत निवेश किया है।

चीन ने कम समय में एसआईसीए देशों में लगातार पैठ बनाई है और आज इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। हालांकि ताइवान के एसआईसीए के साथ आधिकारिक संबंध हैं, लेकिन यह संभव हो सकता है कि निकट भविष्य में चीन इसे बदलने का प्रयास कर सकता है। चीन संभवत: अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शेष तीन एसआईसीए सदस्य देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा।

6. भारत-एसआईसीए संबंध:

वर्तमान वास्तविकताएं और भविष्य की दिशाएं

6क एसआईसीए के साथ भारत के संबंध

आर्थिक संबंध मध्य अमरीकी देशों के साथ भारत के संबंधों का आधार रहे हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें सहयोग बढ़ाने के लिए खोजा जा सकता है। महामारी ने वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बना दिया है; हालांकि, जैसा कि दुनिया झटके से उभरती है, कोई पाता है कि एलएसी क्षेत्र के भीतर, मध्य अमरीका की अर्थव्यवस्थाओं ने लचीलापन दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, महामारी की शुरुआत के बाद से, मध्य अमरीका, पनामा और डोमिनिकन गणराज्य (सीएपीडीआर) की अर्थव्यवस्थाएं लैटिन अमरीका में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से थीं। 2021 तक, पनामा को छोड़कर सभी ने पूर्व-महामारी उत्पादन स्तरों को पार कर लिया था। यह सुदृढ़ वसूली आंशिक रूप से अधिकारियों की तेज, व्यापक और कई मामलों में, अभूतपूर्व नीतिगत प्रतिक्रियाओं का परिणाम थी। इनमें आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने और सामाजिक समर्थन और स्वास्थ्य खर्च के तेज विस्तार में मदद करने के लिए मौद्रिक नीति दरों में ऐतिहासिक कटौती शामिल थी। क्षेत्र के अपेक्षाकृत उच्च खुलेपन और प्रेषण पर निर्भरता के बीच अमरीका की वसूली जैसे बाहरी कारकों ने भी सुधार में योगदान दिया। रिकवरी को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, एक विनाशकारी तूफान के रूप में प्राकृतिक है जिसने जीवन का नुकसान किया है और नुकसान पहुंचाया है। दूसरा संकट, यूक्रेन में संकट के रूप में मानव निर्मित है। ऊर्जा की कीमतों और खाद्य कीमतों में वृद्धि का क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है।

आर्थिक संबंध मध्य अमरीकी देशों के साथ भारत के संबंधों का आधार रहे हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें सहयोग बढ़ाने के लिए खोजा जा सकता है।

चुनौतियों का मतलब है कि इस क्षेत्र के पास अपने पारंपरिक भागीदारों से व्यापार विविधीकरण के मुद्दों को संबोधित करते हुए घरेलू सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अवसर है। मध्य अमरीका की प्राथमिकता सुदृढ़, टिकाऊ आर्थिक विकास को बहाल करने के लिए अपने गहरे आर्थिक संकुचन से उबरना है और जैसा कि वे एशिया की ओर देखते हैं, वे क्षेत्र की दो शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं-भारत और चीन को देख रहे हैं।

6ख एसआईसीए के साथ भारत के संबंध: भविष्य का निर्माण संबंध तैयार

पिछले दो दशकों में अलग-अलग एसआईसीए सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बढ़े हैं और मध्य अमरीकी देशों ने भारत और क्षेत्र के बीच अधिक जुड़ाव का आह्वान किया है।

बेलीज, पूर्व में ब्रिटिश होंडुरास, मध्य अमरीका में एकमात्र अंग्रेजी बोलने वाला देश है और राष्ट्रमंडल और भारत का सदस्य है और बेलीज मैत्रीपूर्ण, गर्म और सौहार्दपूर्ण संबंधों का लाभ उठाते हैं। बेलीज पारंपरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर भारत का समर्थन करता है, और इसके विपरीत। एकमात्र देश के रूप में जिसके पास कोई स्थायी सेना नहीं है, कोस्टा रिका इस क्षेत्र में अद्वितीय है। यह वह देश भी है जिसने अपनी जैव विविधता की रक्षा पर जोर दिया है और 1984 में अपने वन आवरण को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 2011 में 50 प्रतिशत से अधिक करके वनों की कटाई को सफलतापूर्वक उलट दिया है। इसका एक सफल संरक्षण कार्यक्रम है और जैव विविधता हॉटस्पॉट की सुरक्षा, संसाधनों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण के लिए सबक प्रदान करता है। भारत इस छोटे गणतंत्र के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों के भीतर इस पहलू का पता लगा सकता है।

भारत डोमिनिकन गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इसने 2022 में सैंटो डोमिंगो में अपना दूतावास खोला। दोनों देश अंतरिक्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और साइबर सुरक्षा, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण और सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) में डोमिनिकन गणराज्य के साथ एक सुदृढ़ साझेदारी की ओर भी देखता है। भारत और अल सल्वाडोर दोनों ने अपने संबंधों को विस्तारित और गहरा करने में गहरी रुचि दिखाई है। दोनों देशों ने हाल ही में अपना तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया जिसमें स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश सहित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ करने और अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थितियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर काम करने की आवश्यकता पर भी विचार साझा करते हैं।

ग्वाटेमाला के साथ भारत के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, जिसमें 2018 में उपराष्ट्रपति नायडू की भारत यात्रा है। मई 2021 में, राजनीतिक परामर्श तंत्र की दूसरी बैठक-एफओसी बैठकें-सचिव पूर्वी मैडम रीवा गांगुली और उप मंत्री कार्लोस रामिरो मार्टिनेज की भागीदारी के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थीं। उसी वर्ष जुलाई में विदेश राष्ट्र मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन ने ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री पेड्रो ब्रोलो के साथ बैठकों के लिए यात्रा की, जिसमें राष्ट्रपति अलेजांद्रो गियामत्तेई की शिष्टाचार भेंट भी शामिल थी। निवेश क्षेत्र में, यह ध्यान देने योग्य है कि ग्वाटेमाला ने "ग्वाटेमाला नो से डेटीन" (ग्वाटेमाला नहीं रुकता है) मंत्र के तहत महत्वपूर्ण रणनीतियों को उत्पन्न किया है जो दुनिया भर के उद्यमियों को नियरशोरिंग की अवधारणा के तहत इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें भारत कोई अपवाद नहीं है[97]। रणनीति के तहत ग्वाटेमाला ने चार क्षेत्रों की पहचान की है जिनके लिए यह क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा-दवा, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विनिर्माण और कंपनी सेवाएं। ये सभी क्षेत्र हैं जिनमें भारत की विशेषज्ञता है और वे अधिक निवेश की संभावना तलाश सकते हैं। विदेश राष्ट्र मंत्री मीनाक्षी लेखी की 2022 की पनामा, होंडुरास और चिली की यात्रा ने उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति

प्रदान की। यह किसी भारतीय मंत्री की होंडुरास की पहली यात्रा थी और जबकि बाजार के आकार के कारण आर्थिक संबंध सीमित हो सकते हैं, भारत और होंडुरास सहयोग के अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा क्षेत्र, कृषि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और भारत अपनी भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि भूमि पट्टे की उपलब्धता का पता लगा सकता है।

भारत ने निकारागुआ द्वारा नई दिल्ली में अपने दूतावास को फिर से खोलने के फैसले का स्वागत किया है। (निकारागुआ का भारत में एक दूतावास था जिसे 1990 में बंद कर दिया गया था)। फिनटेक क्षेत्र में सहयोग की बढ़ती संभावनाओं पर बाद में इस शोध-पत्र में चर्चा की गई, जो दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया क्षेत्र प्रदान करती है। भारत और पनामा के बीच सौहार्दपूर्ण, भावभीने और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो आपसी समझ और बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और सर्वांगीण सहयोग पर आधारित हैं। भारत-पनामा कनेक्शन मध्य अमरीकी क्षेत्र में सबसे पुराना है, उन्नीसवीं शताब्दी में जब भारतीयों के समूह बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में पनामा रेलवे और बाद में पनामा नहर के निर्माण पर काम करने आए थे। पनामा मध्य अमरीका का पहला देश भी है जहां भारत ने 1973 में एक निवासी मिशन की स्थापना की थी। तब से, भारतीय मूल के लगभग 15000 व्यक्तियों ने पनामा को अपना घर बनाया है जिसने दो समृद्ध संस्कृतियों के बीच बातचीत के स्तर को बढ़ाने में मदद की है[98]। जिस कारक ने संबंधों में निकटता प्राप्त करने में मदद की है, वह लोकतंत्र, बहुसंस्कृतिवाद और धर्मनिरपेक्षता के साझा सामान्य मूल्य और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का सामान्य उद्देश्य रहा है। दोनों देश एकजुटता, समानता, प्रभावकारिता, पारस्परिक हितों और स्थिरता जैसे मानदंडों के आधार पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग के सुदृढ़ समर्थक भी बने हुए हैं। पश्चिमी गोलार्द्ध के केंद्र में पनामा की सामरिक स्थिति और इसकी खुली अर्थव्यवस्था, जैसा कि इसके असंख्य एफटीए द्वारा संकेत दिया गया है, इसे लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति देकर वैश्विक विकास को देखने वाली भारतीय कंपनियों के लिए एक आदर्श स्प्रिंगबोर्ड बनाता है, जिनके साथ भारत का अभी तक कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, एमएसएमई और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापार समझौते[99] नहीं हैं।

एसआईसीए के साथ भारत के जुड़ाव को इस सदी की शुरुआत में देखा जा सकता है जब भारत ने 2004 में नई दिल्ली में एक बैठक के लिए एसआईसीए के सदस्य देशों की मेजबानी की थी।

हालांकि, व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र के देश आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हालांकि, एसआईसीए क्षेत्रीय समूह के माध्यम से एक सामूहिक रूप से उन्होंने बताया है कि वे भारत को दोनों क्षेत्रों के साथ अपने गहरे जुड़ाव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अमरीका और यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं। जबकि भारत यूरोपीय संघ और यूरोपीय देशों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, एसआईसीए भारत को अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक और अवसर प्रदान करता है। भारत ऐसे क्षेत्रों में एसआईसीए

राष्ट्रों के साथ त्रिपक्षीय संबंधों का भी पता लगा सकता है, एसआईसीए राष्ट्रों ने विकास को सुविधाजनक बनाने और भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए एक अतिरिक्त क्षेत्रीय भागीदार के रूप में भारत को सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का सदस्य बनने के लिए भी आमंत्रित किया है। इन फायदों से अवगत भारत व्यापार और वाणिज्य और निवेश के माध्यम से अपने संबंधों को गहरा करने की भी संभावना तलाश रहा है।

एसआईसीए के साथ भारत के जुड़ाव को इस सदी की शुरुआत में देखा जा सकता है जब भारत ने 2004 में नई दिल्ली में एक बैठक के लिए एसआईसीए के सदस्य देशों की मेजबानी की थी। विचार-विमर्श का परिणाम एक घोषणा थी जिसमें एसआईसीए और भारत के बीच राजनीतिक सहयोग और संवाद के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई थी। यह यात्रा भारत और लैटिन अमरीका और कैरिबियन के बीच विदेशी संबंधों में एक पथ-प्रदर्शक थी क्योंकि यह मध्य अमरीका द्वारा भारत को भेजे गए किसी भी मंत्रिस्तरीय और उच्च-स्तरीय अभ्यावेदन के लिए एक पहली थी। एसआईसीए का संदेश भौगोलिक दूरी और भाषाई बाधाओं से उत्पन्न अब तक की बाधाओं को पार करते हुए भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बढ़ा हुआ प्रयास है। सहयोग की दिशा में संगठित ऊर्जा का दूसरा दौर 2008 में देखा गया था जब मध्य अमरीकी देशों ने 2025 में बैठकों के तीसरे दौर के साथ दोनों क्षेत्रों के बीच मौजूदा संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया था[100]। इन बैठकों के परिणामस्वरूप भारत और एसआईसीए पारस्परिक हित के क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम थे और भारत ने कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित गतिविधियों, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने की पेशकश की।

जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह शोध-पत्र सहयोग के कुछ क्षेत्रों की पहचान करता है जिन्हें संबंधों के भविष्य के लिए तैयार करने के लिए खोजा जा सकता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां एसआईसीए राष्ट्र और भारत एक साथ काम कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन बनाने के प्रयासों में है। मध्य अमरीका प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के लिए असाधारण रूप से कमजोर है। यह पहले से ही तूफान, बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय क्षरण, कोरल ब्लीचिंग और सूखे का सामना कर रहा है, मौसम की अस्थिरता और समुद्र के तापमान में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए प्रभाव तेज होने की संभावना है। इसलिए, लचीलापन-निर्माण की योजना, और पर्यावरण सुधारों पर विकास भागीदारों के साथ जुड़ाव, इस क्षेत्र के नीति निर्माताओं के लिए केंद्रीय बन गया है। भारत जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में सबसे आगे रहा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण में सकारात्मक कार्रवाई करके प्रतिबद्धता और नेतृत्व प्रदर्शित किया है। घरेलू मोर्चे पर, भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को अपने सकल घरेलू उत्पाद[101] के 21 प्रतिशत तक कम कर दिया है और पेरिस प्रतिबद्धताओं के तहत किए गए वादे के अनुसार 2030 तक 33-35 प्रतिशत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है[102]। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत आईएसए की स्थापना के साथ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक जुटाना है। आईएसए ने अगस्त 2020 में "वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड" योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य 140 देशों को एक ट्रांस-नेशनल ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। भारत 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में सीडीआरआई के शुभारंभ में भी महत्वपूर्ण था। मध्य

अमरीकी राष्ट्र आईएसए के सदस्य हैं और जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये भारत और एसआईसीए राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी काम कर सकते हैं ताकि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधान, बुनियादी ढांचे से संबंधित अच्छी प्रथाओं, जलवायु लचीलापन और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप लोगों के संभावित विस्थापन पर शोध और विकास के लिए मिलकर काम किया जा सके।

एक ऐसा क्षेत्र जहां एसआईसीए राष्ट्र और भारत एक साथ काम कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन बनाने के प्रयासों में है।

सतत आर्थिक विकास के मापदंडों के भीतर, भारत महासागर संसाधनों के सतत उपयोग या समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के लिए साझेदारी विकसित करना चाहता है। एसआईसीए राष्ट्र दो महासागरों-अटलांटिक और प्रशांत पर कब्जा करते हैं, इस क्षेत्र के देश आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर एक साथ काम करते हैं। पनामा नहर के परिणामस्वरूप पनामा इस क्षेत्र के समुद्री केंद्र के रूप में उभरा है। भूमि और समुद्र पर दृढ़ संरक्षण प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ एक साहसिक ऊर्जा संक्रमण योजना के माध्यम से, पनामा दुनिया के तीन कार्बन-नकारात्मक देशों में से एक बन गया है। पनामा महासागर संसाधनों के सतत उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग, प्लास्टिक अपशिष्ट और समुद्री प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण पर्यटन और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए वन्यजीव निवास स्थान और पर्यावरण नियमों को संरक्षित करने के लिए पारिस्थितिक कार्यक्रमों के माध्यम से समुद्री और हरी अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है[103]। ये पहल एक दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं जो इस विषय पर भारत के विचारों के समान है। समुद्री अर्थव्यवस्था पर अपने मसौदा नीति ढांचे में, नीति तटीय क्षेत्रों के सतत विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के सभी क्षेत्रों (जीवित, निर्जीव संसाधन, पर्यटन, समुद्री ऊर्जा, आदि) के इष्टतम उपयोग की परिकल्पना करती है[104]। जैसा कि भारत समुद्री अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य क्षेत्र बनाता है, यह मत्स्य पालन, शिपिंग, पर्यटन, गहरे समुद्र खनन, अपतटीय ऊर्जा संसाधनों, समुद्री अनुसंधान, महासागर संरक्षण और महासागर विज्ञान सहित महासागर-आधारित क्षेत्रों में सहयोग के लिए अवसरों का एक 'महासागर' प्रदान करता है।

उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित लेकिन उन तक सीमित नहीं हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग में संभावनाएं हैं। आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास के बीच एक सुसंगत लिंक है। उपग्रहों का उपयोग मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम चेतावनी, पर्यावरणीय हॉटस्पॉट की निगरानी, दूरसंचार और ई-शिक्षा को संबोधित करने के लिए किया गया है। जैसा कि अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे क्षेत्र के राष्ट्र अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष उद्योग को देखते हैं, भारत इस क्षेत्र में एक स्वाभाविक भागीदार है। भारत उपग्रह रिमोट सेंसिंग और संचार दोनों में एंड-टू-एंड क्षमता विकसित करने में विश्व के नेताओं में से एक रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने संचार के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) और पृथ्वी अवलोकन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन (आईआरएस) उपग्रहों जैसे

अत्याधुनिक अंतरिक्ष अवसंरचना के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। मई 2017 में, भारत ने सार्क या दक्षिण एशिया उपग्रह लॉन्च किया। 2,230 किलोग्राम का संचार अंतरिक्ष यान एक ऐसे क्षेत्र में संचार, प्रसारण और इंटरनेट सेवाओं, आपदा प्रबंधन, ईमेडिसिन, टेली-शिक्षा और मौसम पूर्वानुमान का समर्थन करेगा जो भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, सीमित तकनीकी संसाधनों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके एप्लिकेशन रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हैं और भारत के पड़ोसी इसके एप्लिकेशन का मुफ्त में उपयोग करते हैं। भारत अपने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बुनियादी ढांचे की योजना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आपातकालीन संचार, आपदा प्रबंधन सहायता और अंतरिक्ष और वायुमंडलीय विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने के लिए अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जानकारी का उपयोग कर रहा है। भारत और एसआईसीए राष्ट्र अंतरिक्ष सहयोग की संभावना तलाश सकते हैं क्योंकि वे समान लक्ष्यों को साझा करते हैं।

सहयोग के प्रमुख स्तंभों में से एक खाद्य सुरक्षा हो सकता है।

बढ़ती तकनीकी विकास साझेदारी का संरचना और वित्तीय क्षेत्र के संचालन के रूप पर प्रभाव पड़ता है, जो अपने उपयोगकर्ताओं के लिए तत्काल प्रतिक्रियाओं के साथ अधिक स्वचालित और सुलभ पारिस्थितिकी तंत्र की ओर इसके विकास को तेज करता है। कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया को जो बदलाव झेलने पड़े हैं, उसके बाद सेवा प्रदाताओं, सरकारी संस्थाओं, पारंपरिक वित्तीय संस्थानों, निजी संस्थाओं और आम जनता की ओर से फिनटेक क्षेत्र में रुचि बढ़ी है; यह क्षेत्र जो उसके परिणामस्वरूप पूर्वगामी लाभ और अवसर प्रदान करता है, [105]। भारत को विश्व स्तर पर एक सुदृढ़ फिनटेक हब के रूप में पहचाना जाता है, और जैसे-जैसे भारतीय उद्यमशीलता परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, अधिक फिनटेक उपयोग-नेतृत्व वाले व्यवसायों को विकसित किया जाएगा, जिसमें अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। आशाजनक भारतीय फिनटेक बाजार के 2030 तक 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है, जो 2021 में 31 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारतीय फिनटेक द्वारा नवाचार ने आज देश में देखे जा रहे वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्रदान की है। लैटिन अमरीका में, ब्राजील, मैक्सिको और पेरू जैसे देशों में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। लैटिन अमरीका में सबसे बड़ी फिनटेक- न्यूबैंक ने सार्वजनिक होने से पहले 2021 में प्री-आईपीओ वित्तपोषण में $ 750 मिलियन जुटाए और आज इसका मूल्य $ 45 बिलियन से अधिक है[106]। क्षेत्र के भीतर अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में इस्तेमाल करने के साथ प्रयोग किया है और देश में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार किया है। क्षेत्र के अन्य देश भी इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि से अछूते नहीं हैं क्योंकि पनामा इस क्षेत्र के लिए फिनटेक हब बनने की होड़ में है। निकट भविष्य में फिनटेक क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रों के साथ, यह भारत और मध्य अमरीका दोनों के साथ विचारों, निवेश और सहयोग के आदान-प्रदान के लिए सहयोग का एक क्षेत्र प्रदान करता है, जिसमें स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए समान दृष्टिकोण हैं ताकि अभिनव समाधान, अधिक वित्तीय समावेशन, आसान पहुंच और उनके लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में मदद मिल सके।

सहयोग के प्रमुख स्तंभों में से एक खाद्य सुरक्षा हो सकता है। खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की

आबादी को देखते हुए उसके लिए एक चुनौती है। कृषि और पशुधन क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय विकास और सुधारों के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं और भारत और एसआईसीए राष्ट्र उन्नत बीज, उर्वरक, मशीनरी, प्रौद्योगिकी और उत्पादन, विपणन और निर्यात के नवीन तरीकों का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की चुनौतियों को दूर करने के लिए किफायती और व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। यह देखते हुए कि उत्पादकता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत की ताकत है, दोनों पक्ष कृषि-टेक, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं।

एसआईसीए ने जलवायु स्मार्ट कृषि रणनीति 2018-2030 की रूपरेखा तैयार की है। कृषि क्षेत्र के लिए रणनीति का उद्देश्य बाजारों से बढ़ती मांग का जवाब देने के लिए और साथ ही, विश्व आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा की गारंटी देने के लिए, कुशल और टिकाऊ तरीके से अधिक भोजन का उत्पादन करने की चुनौती का सामना करना है। जलवायु स्मार्ट कृषि के तीन स्तंभ हैं जो खाद्य और पोषण सुरक्षा के पक्ष में हैं: i) कृषि उत्पादकता और आय (खाद्य सुरक्षा) में लगातार वृद्धि; ii) जलवायु परिवर्तन (अनुकूलन) के लिए लचीलापन को अनुकूलित करना और निर्माण करना; (iii) उत्पादन प्रणालियों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और/या हटाना, जहां संभव हो (शमन)[107]।

भारतीय कृषि को आम तौर पर 'हरित क्रांति' के साथ पहचाना जाता है जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिससे राष्ट्र को घरेलू खाद्य उत्पादन में बड़ी प्रगति करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली। इसने भारत को खाद्य-कमी वाले राष्ट्र से खाद्य-अधिशेष, निर्यात-उन्मुख देश में बदल दिया। हालांकि, अब देश दूसरी पीढ़ी की समस्याओं का सामना कर रहा है, विशेष रूप से स्थिरता, पोषण, नई कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, खेती पर निर्भर आबादी के आय स्तर से संबंधित है। कृषि नई और अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। सरकार लगातार इन चुनौतियों का सामना कर रही है, और यह चिंताओं को दूर करने के लिए प्रासंगिक घरेलू नीति का निर्माण कर रही है, यह भविष्य के लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए भागीदार देशों के साथ भी प्रयास कर रही है।

एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जो प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है और कृषि सहित अपने विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी में निवेश की तलाश कर रहा है, भारत एक प्राकृतिक भागीदार है। भारत खुद को एक प्रौद्योगिकी स्टार्ट अप हब के रूप में विकसित कर रहा है और मूल्य श्रृंखला सेवाओं का निर्माण कर रहा है। भारत और एसआईसीए राष्ट्र इन देशों में भूमि की खरीद सहित निवेश के अवसरों का भी पता लगा सकते हैं।

जैसा कि भारत और एसआईसीए राष्ट्र कृषि में सहयोग के अवसरों का पता लगाते हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की चुनौतियों का भी समाधान करना होगा, जिससे यह सहयोग का एक और क्षेत्र बन जाएगा। एसआईसीए देश अपनी प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति दोनों के लिए, गरीबी और सामाजिक घाटे के अपने उच्च स्तर के लिए वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए सबसे कमजोर क्षेत्रों में से एक हैं। यह क्षेत्र पहले से ही भारी बारिश और तूफान, सूखे और नई अज्ञात चरम घटनाओं के नए शासनों के अधीन है जो सार्वजनिक संसाधनों,

देशों के सामाजिक और आर्थिक आधार पर प्रभाव डाल रहे हैं और क्षेत्रीय लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डाल रहे हैं[108]। भारत ने 2008 में अपना राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन भी शुरू किया है और तब से जलवायु को अपनी पर्यावरण नीति और विकास एजेंडे के केंद्र में रखा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की कुंजी के रूप में संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के स्वस्थ और टिकाऊ तरीके का प्रचार करने के लिए एलआईएफई-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पहल शुरू की है[109]।

वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में, भारत और एसआईसीए वैश्विक दक्षिण के सदस्यों पर जलवायु परिवर्तन अनुसंधान पर ध्यान देने में योगदान देते हैं। बढ़ते अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त अंतर को देखते हुए, विशेष रूप से अनुकूलन के लिए, विकासशील देशों के लिए पूरक व्यवस्थाओं की जांच करना महत्वपूर्ण हो जाता है जो उन्हें अपने जलवायु लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। दक्षिण-दक्षिण सहयोग और आर्थिक एकीकरण विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ा सकता है, खासकर क्षेत्रीय विकास बैंकों के माध्यम से; हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और हरित निवेश की सुविधा; और जलवायु अनुकूलन के लिए सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी कमजोरियों को कम करने के लिए एलडीसी और एसआईडी में क्षमता विकसित करना[110]।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग उत्तर-दक्षिण त्रिकोणीय सहयोग के साथ समावेशी विकास के लिए मार्ग बनाने का एक अभिनव साधन है, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के दायरे में वे विशेषज्ञों को बुला सकते हैं और 'इवेंट एट्रिब्यूशन' विज्ञान के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए समर्पित दक्षिण-नेतृत्व वाले अनुसंधान संघ के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह जलवायु विज्ञान को समृद्ध करेगा, अधिक कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करेगा, विकासशील देशों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण करेगा, और एल एंड डी (नुकसान और क्षति) ढांचे को सुदृढ़ करेगा। यह भारत और एसआईसीए को व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग के माध्यम से न केवल एक साथ काम करने बल्कि अन्य देशों के साथ साझेदारी करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस दक्षिण-दक्षिण सहयोग को अन्य क्षेत्रों में भी खोजा जा सकता है, जिससे भारत और एसआईसीए राष्ट्रों को सहकारी दृष्टिकोण बनाने और आर्थिक लिंक के साथ विकास त्मक विकल्प का विस्तार करने की अनुमति मिल सके। दक्षिण-दक्षिण सहयोग उत्तर-दक्षिण त्रिकोणीय सहयोग के साथ समावेशी विकास के लिए मार्ग बनाने का एक अभिनव साधन है, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। उदाहरण के लिए, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत सामूहिक हित को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक और क्षेत्रीय दूरियों को पार कर रहा है। आईबीएसए बहुपक्षीय सुधारों पर परामर्श, वस्तुओं और सेवाओं के अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक मंच है। ब्रिक्स (ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) एक और ऐसा संगठन है जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है।

उपरोक्त सहयोग के कुछ क्षेत्र हैं जो इस क्षेत्र और भारत के बीच संबंधों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को सबसे आगे लाते हैं। इन क्षेत्रों में संबंधों को सीमित करने का सुझाव नहीं है, फिर भी, विचारों के मुक्त प्रवाह के माध्यम से हमारे लोगों से लोगों को जोड़ने में मदद करने के लिए उनका पता लगाया जा सकता है, भविष्य के लिए तैयार और सक्षम संबंधों की नींव रखते हुए अधिक निजी क्षेत्र को एक-दूसरे के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करके व्यापार से व्यावसायिक संबंधों को बढ़ाया जा सकता है।

7. निष्कर्ष

एलएसी क्षेत्र उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसमें भारत ने बिना किसी मतभेद के सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हैं। तथ्य यह है कि क्षेत्र के देशों और भारत के बीच कोई मतभेद नहीं हैं, इसका मतलब यह भी है कि संबंधों को वह ध्यान नहीं मिला है जिसके वे पात्र हैं। एसआईसीए के साथ भारत के संबंध भी उसी रास्ते पर चलते हैं। जबकि वैश्विक दृष्टिकोण और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि में समानताएं हैं, संबंध ज्ञान की सामान्य कमी से बाधित रहे हैं, जिसका अर्थ है कि न तो दूसरे की क्षमता और सामरिक जुड़ाव की सुसंगत नीति के बारे में पता है। हालांकि, ये समस्याएं बनी हुई हैं, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि व्यावहारिक वित्तीय बाधाएं थीं जिन्होंने एक-दूसरे के रडार में उपस्थिति को भी बाधित किया है। एक विकासशील देश के रूप में जो अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहा था, भारत के पास एलएसी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को तेजी से बढ़ाने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। इस क्षेत्र पर ध्यान इस तथ्य से भी बाधित हुआ कि भारत के निकटतम पड़ोस और भीतर उत्पन्न होने वाले सुरक्षा मुद्दों ने नए स्वतंत्र राष्ट्र को व्यस्त रखा था। शीत युद्ध की ब्लॉक राजनीति गहरे संबंधों के विकास के लिए अनुकूल नहीं थी और फिर भी अवसर पैदा होने पर भारत और क्षेत्र के देशों ने एक साथ काम करना जारी रखा। शीत युद्ध के बाद के वर्षों में भू-राजनीतिक वातावरण में बदलाव और आर्थिक उदारीकरण के साथ, भारत एशिया में एक आर्थिक दिग्गज के रूप में उभरा। यह आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।

अपनी बढ़ी हुई आर्थिक क्षमता के अनुरूप भारत ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर अपने विचारों को व्यक्त करने, उजागर करने और साझा करने के लिए अपनी वैश्विक विदेश नीति का विस्तार किया है। यह तेजी से एक आवाज बन रहा है जिसे भू-राजनीतिक, भू-अर्थशास्त्र और भू-सामरिक मुद्दों पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि भारत अपनी विदेश नीति की नींव पर आगे बढ़ रहा है, इसने उस क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए लगातार कदम उठाए हैं जो परिधि में बना हुआ है। क्षेत्र और भारत के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की नई अभिव्यक्ति के साथ एलएसी क्षेत्र पर भारत के ध्यान में एक स्पष्ट बदलाव आया है। भारत के राष्ट्रपति ने चिली और बोलीविया की राजकीय यात्रा की, जबकि उपराष्ट्रपति ने पराग्वे और कोस्टा रिका का दौरा किया और अजरबैजान में गुट निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की वार्षिक बैठक के मौके पर क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक भी की। इसके साथ ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की ब्राजील यात्रा के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर न्यूयॉर्क में कैरीकॉम नेताओं के साथ उनकी बैठक भी थी। तब से लैटिन अमरीकी नेताओं द्वारा दो राजकीय यात्राएं हुई हैं, जिनमें 2019 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की यात्रा भी शामिल है, जहां कई समझौता ज्ञापनों

पर हस्ताक्षर किए गए थे और साथ ही दोनों राज्यों द्वारा सामरिक साझेदारी की ओर बढ़ने की घोषणा की गई थी। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के साथ भारत और ब्राजील के बीच मौजूदा सामरिक साझेदारी के लिए एक नई कार्य योजना भी थी[111]।

क्षेत्र और भारत के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की नई अभिव्यक्ति के साथ एलएसी क्षेत्र पर भारत के ध्यान में एक स्पष्ट बदलाव आया है।

चुनौतियों को दूर करना

बहरहाल, कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन्हें भारत को एलएसी क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें एसआईसीए भी शामिल है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वह इसे एक क्षेत्र के रूप में देखे या उन्हें व्यक्तिगत राज्यों के रूप में देखे। यह समझने की जरूरत है कि एलएसी क्षेत्र एक मोनोलिथ संपूर्ण नहीं है, बल्कि उन देशों के साथ एक विविध क्षेत्र प्रस्तुत करता है जिनकी अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं, सामरिक हित और आर्थिक आवश्यकताएं हैं। जैसा कि इस पत्र में चर्चा की गई है, यह एसआईसीए के भीतर भी स्पष्ट है। हालांकि भारत को इस क्षेत्र को समग्र रूप से देखने और एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है जो विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए हो, लेकिन उसे प्रत्येक देश की राजनीतिक स्थापना, इसकी सुरक्षा आवश्यकताओं और व्यक्तिगत देश के प्रति अपनी नीतियों को तैयार करने के लिए अपनी आर्थिक दृष्टि को भी समझना होगा। इस मेगा-क्षेत्र के भीतर सामाजिक और आर्थिक विविधता और विकास की तीव्र गति को ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि भारत इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव के लिए अपनी दृष्टि का निर्माण कर रहा है। भारत ने इस क्षेत्र के बड़े देशों के साथ अपने संबंधों पर जोर दिया है और उसके संबंध मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको पर केंद्रित हैं। हालांकि, जैसा कि भारत महाद्वीप के साथ अपने संबंधों का विस्तार करता है, उसे मध्य अमरीका और कैरिबियन में अपने सहयोगियों के साथ भी जुड़ना पड़ता है। अतीत में अपनी आर्थिक बाधाओं के कारण, जिसने इस क्षेत्र में अपनी राजनयिक उपस्थिति को सीमित कर दिया है, भारत ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, फिर भी, यह अपर्याप्त बना हुआ है और भारत को जल्द से जल्द इस अंतर को दूर करने की आवश्यकता है।

भारत के लिए एक बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति बनी हुई है।

भारत के लिए एक बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति बनी हुई है। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहुंच के मामले में भारत चीन से पीछे है। चीन, अब एलएसी देशों के लिए एक सक्रिय और निर्विवाद भागीदार है और ब्राजील, पेरू और चिली सहित क्षेत्र के कई देशों के लिए सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, और वेनेजुएला, बोलीविया और

अर्जेंटीना जैसे अन्य देशों के लिए एक प्रमुख निवेशक और ऋणदाता है। चीन भी एसआईसीए देशों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन ने इस क्षेत्र के प्रति एक व्यापक नीति तैयार की है जिसे चीन और एलएसी के बीच वैचारिक और राजनीतिक संबंधों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे समय में जब दुनिया एक प्रमुख वैश्विक नायक के रूप में चीन के उदय को देख रही है, इसकी लगातार बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव पर भारत द्वारा नजर रखने की आवश्यकता है, विशेषकर जब भारत अपने राजनयिक पदचिह्न का विस्तार कर रहा है और कई मुद्दों पर दुनिया के साथ जुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मध्य अमरीका के देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत चीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है और न ही इसकी आवश्यकता है, लेकिन उसे सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से अपनी सॉफ्ट पावर ताकत के साथ खेलना जारी रखते हुए विज्ञान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी ताकत को उजागर करना होगा।

एक अन्य चुनौती भारत और एलएसी देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की कमी है जो चीन, दक्षिण कोरिया और अमरीका जैसे अन्य भागीदार देशों की तुलना में एक-दूसरे को हानि पहुँचा सकता है, जिनमें से सभी का लैटिन अमरीकी देशों के साथ एफटीए है। एसआईसीए सहित क्षेत्र के देशों ने आर्थिक समझौतों के माध्यम से भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने की मांग की है। भारत और लैटिन अमरीका के बीच प्रत्यक्ष शिपिंग मार्गों की कमी का मतलब है कि मार्ग और देश के आधार पर शिपमेंट में 35 से 75 दिन लग सकते हैं; एक और नुकसान राजनीतिक इच्छाशक्ति की वर्तमान कमी है, जिसे यदि बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक संबंधों का समर्थन और बढ़ावा मिल सकता है[112]।

इन सभी चुनौतियों के बावजूद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत और एलएसी क्षेत्र के देश साझेदार हैं और दुनिया के महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में नई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में कमोबेश एक साथ उभरे हैं और भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को परिभाषित करेंगे। जैसे-जैसे पारस्परिक अवसर उत्पन्न होते हैं, भारत और क्षेत्र के देशों को यह समझना होगा कि वे विवाद से मुक्त लाभकारी संबंध को बढ़ाने और बनाने के लिए इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

एक उदीयमान विकास ध्रुव के रूप में एसआईसीए की समझ का पता लगाने के लिए जागरूकता है
जिसे भारत और एसआईसीए के बीच उत्पादों, सेवाओं और व्यावसायिक हितों की सामंजस्य द्वारा
और रेखांकित किया गया था।

जैसे-जैसे भारत एलएसी क्षेत्र के बारे में अधिक समझ हासिल कर रहा है, यह धीरे-धीरे लेकिन लगातार अपने द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से व्यापक क्षेत्र के साथ जुड़ रहा है, जबकि उप-क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंधों की भी खोज कर रहा है। इसी संदर्भ में भारत एसआईसीए के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। संबंधों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए

जोर देने को उन सरकारों का समर्थन मिला है जिन्होंने हाल के वर्षों में अपने जुड़ाव और सहयोग को तेज किया है। आर्थिक संबंध एसआईसीए राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों का मुख्य स्तंभ बने हुए हैं जैसा कि यह समग्र रूप से व्यापक क्षेत्र के साथ करता है। हालांकि, भारत और एसआईसीए देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं, लेकिन भारत और एसआईसीए राष्ट्रों के बीच बाजार के आकार में अंतर के कारण वे दायरे में सीमित हैं। बहरहाल, एक समूह के रूप में वे सहयोग और निवेश के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करते हैं। एक उभरते विकास ध्रुव के रूप में एसआईसीए की समझ का पता लगाने के लिए जागरूकता है जिसे उत्पादों, सेवाओं और व्यावसायिक हितों की सामंजस्य द्वारा रेखांकित किया गया था। भारत के अनुमानित विकास को देखते हुए, संसाधनों की इसकी अनुमानित आवश्यकता, लोकतांत्रिक और स्थिर राजनीति और दोनों के पारस्परिक विकास के लिए इस क्षेत्र में निवेश करने के प्रयास, इसे एसआईसीए के लिए एक बहुत ही आकर्षक भागीदार बनाते हैं। जैसा कि हम संबंधों के भविष्य के प्रक्षेपवक्र का पता लगाते हैं, एसआईसीए से व्यापार में विविधता लाने के लिए जोर देने को ध्यान में रखते हुए, यह दोनों पक्षों को पारंपरिक क्षेत्र से परे सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों में देखने का सही अवसर प्रदान करता है जो नवाचार को बढ़ावा देगा जो भविष्य का मार्गदर्शन करेगा।

**डॉ. स्तुति बनर्जी, वरिष्ठ अध्येता और डॉ. अर्नब चक्रवर्ती, अध्येता, आईसीडब्ल्यूए। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।*

लेखकों के बारे में

सप्रू
हाउस
पेपर

डॉ. स्तुति बनर्जी, भारतीय वैश्विक परिषद, नई दिल्ली में एक वरिष्ठ अध्येता हैं। परिषद में, डॉ. बनर्जी उत्तरी अमरीका और लैटिन अमरीका और कैरिबियन, इंडो-पैसिफिक और ध्रुवीय क्षेत्र पर अनुसंधान में कार्यरत हैं। इसमें अमरीका और भारत की विदेश नीति और दोनों देशों की ध्रुवीय नीति पर जोर देने के साथ राजनीति, रणनीति और सुरक्षा पर विश्लेषणात्मक लेख तैयार करना शामिल है।

आईसीडब्ल्यूए में शामिल होने से पहले, वे सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज (सीएपीएस), नई दिल्ली में एसोसिएट फेलो थीं। सीएपीएस में वह परमाणु सुरक्षा परियोजना का हिस्सा थी और एशिया के भीतर देशों में परमाणु ऊर्जा के विकास का अध्ययन कर रही थी। कैप्स में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 'सॉफ्ट पावर' की अवधारणा पर भी लिखा है। उन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के लिए रिसर्च इंटर्न के रूप में काम किया है। उन्होंने अमरीकी, कनाडाई और लैटिन अमरीकी अध्ययन प्रभाग, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की है।

डॉ. अर्णब चक्रवर्ती लैटिन अमरीका में विशेषज्ञता रखने वाले आईसीडब्ल्यूए (भारतीय वैश्विक परिषद) में अध्येता हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कनाडाई, अमरीकी और लैटिन अमरीकी अध्ययन केंद्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और आईसीडब्ल्यूए में शामिल होने से पहले थोड़े समय के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय में एक संकाय के रूप में कार्यरत थे। उनके अनेक प्रकाशन है जो अधिकतर लैटिन अमरीकी क्षेत्र से संबंधित है और उन्हें दो विदेशी भाषाओं, जर्मन और स्पेनिश का ज्ञान हैं। उनके अनुसंधान के क्षेत्र में लैटिन अमरीका और स्वदेशी राजनीति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र मशीनरी, लैटिन अमरीकी इतिहास, लैटिन अमरीका और भारत में नागरिक-सैन्य संबंध और लैटिन अमरीका के साथ इसके संबंधों के विषयों पर शामिल हैं। उनके लेख द डिप्लोमेटिस्ट, कूटनीती, द कोस्टा रिकान न्यूज, डिप्लोमेसी एंड बियॉन्ड और द फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी पर प्रकाशित हुए हैं।

इन सभी चुनौतियों के बावजूद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत और एलएसी क्षेत्र के देश साझेदार हैं और दुनिया के महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में नई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में कमोबेश एक साथ उभरे हैं और भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को चतुराई से लेंगे। जैसे-जैसे पारस्परिक अवसर उत्पन्न होते हैं, भारत और क्षेत्र के देशों को यह समझना होगा कि वे विवाद से मुक्त एक लाभकारी संबंध को बढ़ाने और बनाने के लिए इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

पाद-टिप्पणियाँ

[1]मई 11, 2022, अपराजिता पांडे, "भारत - मध्य अमरीका: भविष्य के लिए अवसर," *द फाइनेंशियल एक्सप्रेस*, 11 मई, 2022, https://www.financialexpress.com/defence/india-central-america-opportunities-for-the-future/2520633/, 16 अक्तूबर 2022, को अभिगम्य।

[2]*रीविस्टा कंपल्टेंस डी हिस्टोरिया डी अमरीका,* 2011 "अमरीका के संघीय संघ के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, "यह एक ऐसा देश है, जो अमरीका के लिए है। https://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/article/download/38248/37005/, 1 मई 2022, को अभिगम्य।

[3]के. आर. साईमंड्स, "मध्य अमेरिकी आम बाजार: क्षेत्रीय एकीकरण में एक प्रयोग", *द इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉ क्वाटर्ली*, 1967, खंड 16, संख्या 4, पृष्ठ 911-945.

[4]29 अक्तूबर 1993, ओएएस, विदेश व्यापार सूचना प्रणाली, "प्रोटोकॉलो अल ट्रैटो जनरल डी इंटीग्रेटोसिओन इकोनोमिका सेंट्रोअमरीकाना (प्रोटोकॉलो डी ग्वाटेमाला)", 29 अक्तूबर 1993, http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/Prot.Guatemala93.pdf, 3 मई 2022, को अभिगम्य।

[5]एसआईसीए, "Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES)", 3 अक्तूबर 1994,http://www.sice.oas.org/Trade/sica/PDF/Prot.Guatemala93.pdf, 3 मई 2022, को अभिगम्य।

[6]एसआईसीए, "एक नज़र में एकीकरण", https://www.sica.int/sica/vista_en, 4 मई 2022, को अभिगम्य।

[7]एसआईसीए, "एसआईसीए निकाय और संस्थान", https://www.sica.int/sica/instituciones_en.aspx, 3 मई 2022, को अभिगम्य।

[8]ईसीएलएसी, "मध्य अमरीका में एकीकरण के लिए ईसीएलएसी योगदान", 2019, https://www.cepal.org/sites/default/files/wysiwyg/eclacs_contributions_to_central_americas_integration.pdf, 6 मई 2022, को अभिगम्य।

[9]अमेरिकी विदेश विभाग, "मध्य अमेरिकी सुरक्षा आयोग एस्क्विपुलस शांति समझौता, 6-7 अगस्त, 1987, 25 जुलाई 2001, https://2001-2009.state.gov/t/pm/rls/ fs/4265.htm, 8 मई 2022, को अभिगम्य।

[10]संयुक्त राष्ट्र, अमरीका, अमरीका के जनरल कॉन्सेजो डी सेगुरिडाड, "16 जनवरी 1988 को सैन जोस में राष्ट्रपति के रूप में अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई", 22 जनवरी 1988, https:// peacemaker.un.org/sites/ peacemaker.un.org, 6 मई 2022, को अभिगम्य।

[11]संयुक्त राष्ट्र, 27 फरवरी 1989 को अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में घोषणा की गई। https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org, 6 मई 2022, को अभिगम्य।

[12]पूर्वोक्त

[13]एसआईसीए, "सेंट्रल अमेरिकन कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट (सीसीएडी)", https://www.sica.int/ consulta/entidad, 6 मई 2022, को अभिगम्य।

[14]सीईपीएएल, "एस्ट्रेटिया एनर्जेटिका सस्टेनटेबल सेंट्रोअमरीकाना 2020", https://www.cepal.org/es/ publicaciones/25839-

estrategia-energetica-sustentable-centroamericana-2020, 6 मई 2022, को अभिगम्य।

[15]एसआईसीए, "क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण", https://www.sica.int/Iniciativas/ecosistemas, 6 मई 2022, को अभिगम्य।

[16]एसआईसीए, "सेंट्रल अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी फॉर सोशल डेवलपमेंट (ओसीएडीएस)," https://www.sica.int/ iniciativas/ocades, 5 मई 2022, को अभिगम्य।

[17]एसआईसीए, "खाद्य और पोषण सुरक्षा पर क्षेत्रीय वेधशाला (ओबीएसएएन-आर)। https://www.sica.int/ iniciativas/obsanr, 5 मई, 2022, को अभिगम्य।

[18]एसआईसीए, "ग्रामीणों के लिए रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन। https://www.sica.int/ Iniciativas /mildias, 5 मई 2022, को अभिगम्य।

[19]एसआईसीए, "प्रोयेक्टो अल्टरनेटिवा: एकीकरण और एक दूसरे के शरीर को पुनर्स्थापित करना और सेंट्रोमेरिका में अनियमित रूप से फैलने वाले प्रवासियों को नियंत्रित करना," https://www.sica.int/Iniciativas/migracion, 5 मई 2022, को अभिगम्य।

[20]पूर्वोक्त

[21]एसआईसीए, "प्यूब्लोस ओरिजिनेरियोस," https://www.sica.int/Iniciativas/originarios, 4 मई 2022, को अभिगम्य।

[22]एसआईसीए, “ICRIME en breve,” https://www.sica.int/icrime/inicio, 4 मई 2022, को अभिगम्य।

[23]एसआईसीए के सचिवालय जनरल, "मध्य अमेरिकी सुरक्षा रणनीति", 2011, https://www.europarl. europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dcam/dv/ca_security_s_/ca_security_s_en.pdf, 8 मई 2022, को अभिगम्य।

[24]एसआईसीए, "पीएसआईआर-एसआईसीए पोलिटिका सोशल इंटीग्रल रीजनल डेल एसआईसीए," https://sisca.int/agenda-estrategica/ psir-sica, 4 मई 2022, को अभिगम्य।

[25]डॉयचे वेले, "कोस्टा रिका ने भूमि विवाद पर निकारागुआ पर मुकदमा दायर किया", 17 जनवरी 2017, https://www. dw.com/en/costa-rica-sues-nicaragua-over-land-dispute/a-37154779, 6 मई 2022, को अभिगम्य।

[26]डोमिंगुएज़ et.al, "लैटिन अमरीका में सीमा विवाद", यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, 1 अगस्त 2003, https://www.usip.org/publications/2003/08/boundary-disputes-latin-america, 5 मई 2022, को अभिगम्य।

[27]क्यू कोस्टा रिका, "कोस्टा रिका ने एसआईसीए से वापस ले लिया," 19 दिसंबर 2015, https://qcostarica.com/costa- rica-withdraws-from-sica/, 11 मई 2022, को अभिगम्य।

[28]एसआईईसीए, "सेंट्रोमेरिका (एमएससी) सूची में शामिल होने के लिए यहां क्लिक करें। https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/Lista+casos+presentados.pdf, 3 जून 2022, को अभिगम्य।

[29]सेक्रेटरी जनरल डी एसआईसीए, "ब्रासिल से इनकोर्पोरा अल एसआईसीए और एक अन्य मई या कूपरसिओन", 7 अक्तूबर 2008, https://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=28790&idm=1&ident=1, 3 दिसंबर 2022, को अभिगम्य।

[30]सेक्रेटरी जनरल डी एसआईसीए, "कोलंबिया क्षेत्रीय लोकतंत्र एसआईसीए के लिए संयुक्त राज्य है", 27 सितंबर 2013, https://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=81020&idm=1&ident=1, 3 दिसंबर 2022, को अभिगम्य।

[31]एसईएलए, "कोलंबिया ने सेंट्रोसेंट्रोअमरीका और रिपब्लिक डोमिनिका को एक साथ जोड़ा", नोटिसियास डी सिस्तेमा इकोनॉमिको

लैटिनोअमरीका और डेल कैरिबे,", http://www.sela.org/es/ prensa/servicio-informativo/20140221/si/13594/colombia-coopera-con-centroamerica-y-republica- dominicana-en-la-prevencion-de-la-violencia, 3 दिसंबर 2022, को अभिगम्य।

[32]समाचार एजेंसी एडुआना न्यूज के अनुसार, 'एसआईसीए और कैन ने एकीकरण के लिए एक-दूसरे के संपर्क में आने की कोशिश की है। https:// aduananews.com/sica-y-comunidad-andina-piden-fortalecer-coordinacion-entre-bloques/, 3 दिसंबर 2022, को अभिगम्य।

[33]संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, "मेक्सिको और अमरीका के नागरिकों के बीच एक अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में सेक्रेटारिया जनरल ने कहा, "मैं इस अवसर पर मेक्सिको और एसआईसीए के क्षेत्रीय संगठनों में से एक हूं। https://www. sica.int/consulta/Noticia.aspx?Idn=92284&idm=1, 3 दिसंबर 2022, को अभिगम्य।

[34]गोबिएर्नो डी मेक्सिको, "मेक्सिको के कूपरसियन ऑफ मेक्सिको कॉन सेंट्रो अमरीका और एल कैरिबे", गोबिएर्नो डी मेक्सिको, एक्सिओन्स एंड प्रोग्रामस, 12 अप्रैल 2022, https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/ cooperacion-de-mexico-con-centroamerica, 3 दिसंबर 2022, को अभिगम्य।

[35]अमेरिकी विदेश विभाग, पुरालेख, "मोनरो सिद्धांत, 1823", 20 जनवरी 2009, https://2001-2009.state. gov/r/pa/ho/time/jd/16321.htm, 8 जून 2022 को अभिगम्य।

[36]लियोनार्ड, "मध्य अमरीका और संयुक्त राज्य अमरीका: स्थिरता की खोज", (*जॉर्जिया प्रेस विश्वविद्यालय*), 1991।

[37]पूर्वोक्त

[38]ब्रायन लवमैन, "19वीं शताब्दी में लैटिन अमरीका के प्रति अमेरिकी फोरिगन नीति", *ऑक्सफोर्ड लैटिन अमेरिकी इतिहास*, 7 जुलाई 2016,https://oxfordre.com/latinamericanhistory/view/10.1093/ acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore-9780199366439-e-41?print, 8 जून 2022 को अभिगम्य।

[39]बोवेन, "कट्टरपंथी परिवर्तन की ओर अमेरिकी विदेश नीति: ग्वाटेमाला में गुप्त संचालन, 1950-1954", *लैटिन अमेरिकी परिप्रेक्ष्य,* 1983, खंड 10 संख्या 1, पृष्ठ 88-102.

[40]ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन, यूएस गर्वमेंट, अमेरिकी सरकार, "संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश संबंध, 1958-1960, अमेरिकी गणराज्य, खंड V, दस्तावेज़ 347", https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v05/ d347, 9 जून 2022 को अभिगम्य।

[41]पूर्वोक्त

[42]ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन, यूएस गर्वमेंट, "एलायंस फॉर प्रोग्रेस एंड पीस कॉर्प्स, 1961-1969", https:// history.state.gov/milestones /1961-1968/alliance-for-progress, 9 जून 2022 को अभिगम्य।

[43]पोर्टर, "द एंटरप्राइज फॉर द अमरीका इनिशिएटिव: ए न्यू एप्रोच टू इकोनॉमिक ग्रोथ", *जर्नल ऑफ इंटरअमेरिकन स्टडीज एंड वर्ल्ड अफेयर्स*, 1990, खंड 32, संख्या 4, पृष्ठ 1-12.

[44]जेनिफर मॉरिसन ताव, "ऑपरेशन जस्ट कॉज: युद्ध के अलावा ऑपरेशन के लिए सबक", *रैंड*, 1996, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2007/MR569.pdf, 13 मई 2022 को अभिगम्य।

[45]अमरीका का दूसरा शिखर सम्मेलन 1998 में चिली में आयोजित किया गया था।

[46]सीआरएस रिपोर्ट, यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, "निकारागुआ समायोजन और मध्य अमेरिकी राहत अधिनियम: कठिनाई राहत और दीर्घकालिक अवैध एलियंस", 15 जुलाई 1998, https://www.everycrsreport.com/ files/19980715_98-3_08ea932ffbb 5b70b21888bb84863bfba90bfba25.pdf, 15 मई 2022 को अभिगम्य।

[47]अमेरिकी विदेश विभाग, "इंटर-अमेरिकन डेमोक्रेटिक चार्टर की 20वीं वर्षगांठ", 16 सितंबर 2001, https://www.state.gov/20th-anniversary-of-the-inter-american-democratic-charter/, 17 मई 2022 को अभिगम्य।

[48]जीडब्ल्यू बुश संस्थान, "मध्य अमरीका समृद्धि परियोजना", https://www.bushcenter.org/explore-our- work/developing-leaders/central-america-prosperity.html, 19 जून 2022 को अभिगम्य।

[49]यूएसटीआर का कार्यालय, "सीएएफटीए-डीआर (डोमिनिकन गणराज्य-मध्य अमरीका एफटीए)", https://ustr.gov/trade- agreements/free-trade -agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta, 19 जून 2022 को अभिगम्य।

[50]अमेरिकी विदेश विभाग, "मध्य अमेरिकी क्षेत्रीय सुरक्षा पहल: एक साझा साझेदारी", 27 दिसंबर 2011, https://2009-2017.state.gov/documents/organization/183768.pdf, 22 जून 2022 को अभिगम्य।

[51]अमेरिकी सरकार जवाबदेही कार्यालय, "काउंटरनारकोटिक्स: पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रयासों का अवलोकन", 25 अक्तूबर 2017, https://www.gao.gov/products/gao-18-10, 25 जून 2022 को अभिगम्य।

[52]क्लेयर हैनसेन, "ट्रम्प की सीमा की दीवार का कितना निर्माण किया गया था? यूएसए न्यूज, 7 फरवरी 2022, https:// www.usnews.com/news/politics/articles/2022-02-07/how-much-of-president-donald-trumps-border- wall-was-built, 27 जून 2022 को अभिगम्य।

[53]समझौतों में कहा गया है कि अमरीका में संभावित प्रवासियों को अमरीका पहुंचने से पहले होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर में सुरक्षा के लिए आवेदन करना होगा; अन्यथा उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।

[54]इस नीति को आधिकारिक तौर पर प्रवासी संरक्षण प्रोटोकॉल (एमपीपी) के रूप में जाना जाता है और इसे जनवरी 2019 में लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, ट्रम्प प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रवासियों को सीमा पार करने से रोकने के लिए एक पुराने कानून, शीर्षक 42 को लागू किया। यह कानून संचारी रोगों के प्रसार को रोकने का प्रयास करता है।

[55]शायना ग्रीन, "मेक्सिको नीति में बने रहना कई हफ्तों तक जारी रहेगा, मईओर्कस का कहना है", *पोलितको,* 7 मार्च 2022, https://www.politico.com/news/2022/07/03/remain-mexico-policy-mayorkas- said-00043884, 29 जून 2022 को अभिगम्य।

[56]भले ही उत्तरी त्रिकोण देशों और अमरीका ने प्रवासन पर सहयोग किया, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने प्रवासियों के प्रवाह को रोकने के लिए इन देशों पर दबाव डालने के लिए वित्तीय सहायता रोक दी।

[57]व्हाइट हाउस, "फैक्ट शीट: उपराष्ट्रपति हैरिस ने उत्तरी मध्य अमरीका के लिए कार्रवाई के आह्वान के हिस्से के रूप में नई निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं में $ 1.9 बिलियन से अधिक की घोषणा की", 7 जून 2022, 2022, https:// www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/07/fact-sheet-vice-president- harris-announces-more-than-1-9-billion-in-new-private-sector-commitments-as-part-of-call-to- action-for-northern-central-america/, 24 जून 2022 को अभिगम्य।

[58]पूर्वोक्त

[59]व्हाइट हाउस, "फैक्ट शीट: मध्य अमरीका में प्रवासन के मूल कारणों को संबोधित करने की रणनीति", 29 जुलाई 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/29/fact-sheet- strategy-to-address-the-root-causes-of-migration-in-central-america/, 28 जून 2022 को अभिगम्य।

[60]सीआरएस रिपोर्ट, "मध्य अमेरिकी प्रवासन: मूल कारण और अमेरिकी नीति", 31 मार्च 2022, https:// crsreports. congress. gov/product/pdf/IF/IF11151/7, 29 जून 2022 को अभिगम्य।

[61]वित्त वर्ष 2023 के लिए 986 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुरोध किया गया है।

[62]व्हाइट हाउस, "प्रवासन के कारणों को संबोधित करने, पूरे उत्तर और मध्य अमरीका में प्रवासन का प्रबंधन करने और संयुक्त राज्य अमरीका की सीमा पर शरण चाहने वालों के सुरक्षित और व्यवस्थित प्रसंस्करण प्रदान करने के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय ढांचा बनाने पर कार्यकारी आदेश", 2 फरवरी 2021, https:// www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential- actions/2021 /02/02/executive-order-creating-a- comprehensive-regional-framework-to-address-the-causes-of-migration-to-manage-migration-throughout-north-and-central-america-and-to-provide-safe-and-orderly-processing/, 29 जून 2022 को अभिगम्य।

[63]अमेरिकी विदेश विभाग, "सेंट्रल अमेरिकन माइनर्स (सीएएम) प्रोग्राम", https://www.state.gov/refugee- admissions/central-american-minors-cam-program/, 29 जून 2022 को अभिगम्य।

[64]10 जून 2022, व्हाइटहाउस, "फैक्ट शीट: माइग्रेशन एंड प्रोटेक्शन पर लॉस एंजिल्स घोषणा अमेरिकी सरकार और विदेशी भागीदार डिलिवरेबल्स", 10 जून 2022, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/ statements-releases/2022/06/10/fact-sheet-the-los-angeles-declaration-on-migration-and-protection-u-s-government-and-foreign-partner-deliverables/, 4 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[65]माओ, जियांगलिन et.al, "चीन और क्यूबा: 160 साल और आगे की ओर देखना", *लैटिन अमेरिकी परिप्रेक्ष्य*, 2015, खंड 42, संख्या 6, पृष्ठ 140-152.

[66]पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्रालय, "रियो समूह", 15 नवंबर 2000, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/dqzzywt_665451/2633_665453/2634_665455/200011/ t20001115 _697200.html, 9 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[67]पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्रालय, "राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज फ्रायस से मुलाकात की", 25 मई 2001, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ gjhdq_665435/3447_665449/3538_665158/3540_665162 /200105/t20010525_596733.html, 12 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[68]विशेष रूप से माओ त्से तुंग के शासन के तहत, विचारधारा लैटिन अमरीका के प्रति चीन के दृष्टिकोण का मुख्य चालक थी। ग्वाटेमाला में हस्तक्षेप, पनामा नहर दंगों और क्यूबा क्रांति जैसी घटनाओं ने लैटिन अमरीका में अपनी रुचि को तेज कर दिया।

[69]पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मामलों के मंत्रालय, "हू जिंताओ ब्रासीलिया पहुंचे और ब्राजील की राजकीय यात्रा शुरू की", 12 नवंबर 2004, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ gjhdq_665435/3447_665449/3473_665008/3475_665012/200411 /t20041112_594578.html, 12 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[70]स्टेट काउंसिल, द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, "लैटिन अमरीका और कैरिबियन पर चीन के नीति पत्र का पूर्ण पाठ", 24 नवंबर 2016, http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2016/11/24/ content_281475499069158.htm, 13 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[71]ईसीएलएसी, "चीन का पहला मंच और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों का समुदाय: व्यापार और निवेश पर सहयोग के अवसरों की खोज", *लैटिन* अमरीका *और कैरिबियन के लिए आर्थिक आयोग*, जनवरी 2015, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37578/ S1421103_en.pdf, 10 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[72]लुइस गुइलेर्मो सोलिस, "मध्य अमरीका में चीन के बढ़ते धक्का के पीछे क्या है?", *अमरीका त्रैमासिक,* 1 जुलाई 2021, https://www.americasquarterly.org/article/whats-behind-chinas-growing-push-into- central-america/, 18 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[73]कॉन्स्टेंटिनो उरकुयो, "अमेरिकी दबाव के बावजूद, मध्य अमरीका में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है", *लैटिनोमेरिका21,* 18 जून 2021, https://latinoamerica21.com/en/despite-u-s-pressure-chinas-presence-in-central-america-is-growing/, 19 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[74]चाइना डेली, "चीन-कोस्टा रिका संबंध समृद्ध फल देते हैं", 2 जून 2013, http://www.chinadaily.com.cn/ china/2013xivisit/2013-06/02/content_16557223.htm, 11 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[75]इसाबेला कोटा, "चीन ने शी यात्रा पर कोस्टा रिका को $ 400 मिलियन उधार दिए", *रॉयटर्स,* 3 जून 2013, https://www. reuters.com/article/us-china-costarica-idUSBRE95218820130603, 16 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[76]ओईसी, "कोस्टा रिका-चीन द्विपक्षीय व्यापार", 2020, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/cri/partner/chn, 17 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[77]मैरिएन गुएनॉट, "कोस्टा रिका ने एक चीनी वैक्सीन को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह पर्याप्त प्रभावी नहीं है, क्योंकि चीन का शॉट बढ़ती जांच के दायरे में आता है", *बिजनेस इनसाइडर,* 17 जून 2021, https://www.businessinsider.in/ science/news/costa-rica-rejected-a-chinese-vaccine-saying-it-is-not-effective-enough-as-chinas-shot-come-under-increased- scrutiny/articleshow/83604249.cms, 18 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[78]इवान एलिस, "पनामा में चीन की प्रगति: एक अपडेट", *ग्लोबल अमेरिकन्स,* 14 अप्रैल 2021, https:// theglobalamericans.org /2021/04/chinas-advance-in-panama-an-update/, 17 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[79]पूर्वोक्त

[80]पूर्वोक्त

[81]ओईसी, "पनामा-चीन द्विपक्षीय व्यापार", 2020, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/pan/partner/chn, 17 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[82]सीजीटीएन, "चीन, पनामा ने एफएम की बैठक के रूप में संबंधों में संभावनाओं की सराहना की", 4 अप्रैल 2022, https://news.cgtn.com/ news/2022-04-04/Foreign-ministers-of-China-Panama-meet-in-Anhui-18XbbZwmUOk/index.html, 19 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[83]इवान एलिस, "डोमिनिकन गणराज्य में चीनी जुड़ाव: एक अद्यतन", *डायलॉगो अमरीका*, 23 जुलाई 2021, https://dialogo-americas.com/articles/chinese-engagement-in-the-dominican-republic-an-update/#.Yt-KcHbMLIU, 18 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[84]इवान एलिस, "लैटिन अमरीका और कैरिबियन में चीन की भूमिका", सीएसआईएस, 31 मार्च 2022, https://www.foreign. senate.gov/imo/media/doc/033122_Ellis_Testimony1.pdf, 17 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[85]हुआवेई को मार्च 2021 में डोमिनिकन गणराज्य में 5G नीलामी के लिए पिच करने की अनुमति दी गई है।

[86]इवान एलिस (23 जुलाई 2021)। डोमिनिकन गणराज्य में चीनी जुड़ाव: एक अद्यतन। *संवाद* अमरीका. https://dialogo-americas.com/articles/chinese-engagement-in-the-dominican-republic-an- update/#.Ys-6RXbMLIU, 21 जून 2022 को अभिगम्य।

[87]इवान एलिस, "चीन और अल सल्वाडोर: एक अपडेट", 22 मार्च 2021, *सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज,* https://www.csis.org/analysis/china-and-el-salvador-update, 25 जून 2022 को अभिगम्य।

[88]पूर्वोक्त

[89]ओईसी, "अल सल्वाडोर-चीन द्विपक्षीय व्यापार", 2020, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/slv/partner/chn, 14 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[90]इवान एलिस, "निकारागुआ का चीन के लिए फ्लिप: इस क्षेत्र के लिए इसका क्या मतलब है?" 10 दिसंबर 2021, https:// theglobalamericans.org/2021/12/nicaraguas-flip-to-china/, 17 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[91]शिन्हुआनेट, "शी के विशेष दूत ने नए कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में भाग लिया", 11 जनवरी 2022, https://english.news.cn/20220111/cd28e7eb8875428a82791f6f2f207ef1/c.html, 17 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[92]ओईसी, "निकारागुआ-चीन द्विपक्षीय व्यापार", 2020, https://oec.world/en/profile/bilateral-country/nic/partner/chn, 18 जुलाई 2022 को अभिगम्य।

[93]राकेल कार्वाल्हो, "लैटिन अमरीका में चीन: साथी या शिकारी?, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, 25 मई 2019, https://multimedia.scmp.com/week-asia/article/3011618/beijing-conquest-latin-america/ index.htm, 3 दिसंबर 2022 को अभिगम्य।

[94]जॉर्ज गुआजार्डो et.al। "लैटिन अमरीका में औद्योगिक विकास: चीन की भूमिका क्या है? अटलांटिक काउंसिल, अगस्त 2016, https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2016/08/Industrial_Development_ in_Latin_America_web_0829.pdf, 6 दिसंबर 2022 को अभिगम्य।

[95]जेवियर सैंटिसो, "चीन: एक वेकअप कॉल", मल्टीलैटिनास का दशक, 5 मई 2013, https://www.cambridge.org/core/books/abs/decade-of-the-multilatinas/china-a-wake-up-call/D8CF39CD52709341FBDAAF5AE4E17A9F, 05 दिसंबर 2022 को अभिगम्य।

[96]विश्व बैंक, "मेड इन चाइना? लैटिन अमरीका और कैरिबियन की दीर्घकालिक वृद्धि", सितंबर 2011,, https://www.cambridge.org/core/books/abs/decade-of-the-multilatinas/china-a-wake-up-call/ D8CF39CD5270934 1FBDAAF5AE4E17A9F, 05 दिसंबर 2022 को अभिगम्य।

[97]ग्वाटेमाला और भारत: 50 साल पुराने संबंध मजबूत हो रहे हैं। https://www.financialexpress. com/defence/guatemala-india-50-years-old-relationship-growing-stronger/2354213/, 17 अक्तूबर 2022 को अभिगम्य।

[98]भारतीय दूतावास, पनामा, "भारत-पनामा संबंध"। https://www.indianembassyinpanama.com/ eoipa_pages/NDI1, 17 अक्तूबर 2022 को अभिगम्य।

[99]अहमद शारिक खान, भारत में पनामा के राजदूत डॉ गिल्बर्टो लेरेना गार्सिया के साथ साक्षात्कार, "पनामा और भारत के लिए घनिष्ठ संबंध बनाने का समय आ गया है। https://www.thedollarbusiness.com/magazine/- it-is-time-for-panama-india-to-draw-closer-ties-/45600, 18 अक्तूबर 2022 को अभिगम्य।

[100]डॉ. अपराजिता कश्यप, "भारत-एसआईसीए व्यापार सहयोग"। https://diplomatist.com/2020/01/03/india-sica- trade-cooperation/, 17 अक्तूबर 2022 को अभिगम्य।

[101]उत्सर्जन तीव्रता को कम करना-उत्सर्जन तीव्रता आर्थिक गतिविधि की प्रति इकाई जीएचजी उत्सर्जन का स्तर है, जिसे आमतौर पर जीडीपी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मापा जाता है। यह आमतौर पर गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों का दोहन करके और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाकर किया जाता है।

[102]*द इकोनॉमिक टाइम्स,* 5 मार्च 2021, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and- nation/india-to-meet-its-paris-agreement-commitments-ahead-of-2030-pm-narendra-modi/articleshow/81351882.cms?from=mdr#:~:text=%22India%20is%20well%20on%20track,below%202005%20levels%20by%202030, 18 अगस्त 2021 को अभिगम्य।

[103]मिशन पनामा, "साहसपूर्वक टिकाऊ," https://missionpanama.gob.pa/boldly-sustainable/, 19 अक्तूबर 2022 को अभिगम्य।

[104]प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, "समुद्री अर्थव्यवस्था नीति," 27 जुलाई 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1845257, 18 अक्तूबर 2022 को अभिगम्य।

[105]"फिनटेक बूम और अल सल्वाडोर में इसका विकास," https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a6eee774-bcb6-4b99-a6ea-5a10bd27ce19, 19 सितंबर 2022 को अभिगम्य।

[106]पूर्वोक्त

[107]एसआईसीए, "एसआईसीए क्षेत्र के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि रणनीति (2018-2030)। https://www.cac.int/ sites/default/files/Resumen%20EASAC.%20Ingl%C3%A9s.pdf, 29 नवंबर 2022 को अभिगम्य।

[108]Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (सीसीएडी) and Sistema de la Integración Centroamericana (एसआईसीए), "जलवायु परिवर्तन 2010 पर क्षेत्रीय रणनीति", file:///C:/Users/Dr%20 सौरभ%20 मिश्रा/डाउनलोड/एस्ट्रेटेजिया%20रीजनल%20de%20Cambio%20Climatico%20Ingles%20 (1).pdf, 29 नवंबर 2022 को अभिगम्य।

[109]पीआईबी, "परंपराओं और संरक्षण और संयम के मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के एक स्वस्थ और टिकाऊ तरीके को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की कुंजी के रूप में 'जीवन'-'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' के लिए एक जन आंदोलन शामिल है",https://pib.gov.in/ PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1847812, 29 नवंबर 2022 को अभिगम्य।

[110]व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, "जलवायु अनुकूलन और सतत विकास के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग"। https://unctad.org/system/files/official-document/tcsgdsinf2022d1_ en.pdf, 29 नवंबर 2022 को अभिगम्य।

[111]देविका मिश्रा, सादसीदी ज़ेरपा डी हर्टाडो और अल्बर्टो हर्टाडो ब्रिसेनो, भारत-लैटिन अमरीका संबंधों के पहलू: ऊर्जा सहयोग की भूमिका, *भारत-लैटिन अमरीका में: व्यापार और निवेश संबंध* (यूनिवर्सिड डी लॉस एंडे, अगस्त 2021), https://www.researchgate.net/प्रकाशन/354047195_Capitulo_3_The_facets_of_India-Latin_America_relationship_Role_of_energy_ सहयोग, 18 अक्तूबर 2022 को अभिगम्य।

[112]Hari Seshasayee, “Re-examining India - Latin America ties in an Asian and global context,” Asia Power Watch, एशिया पावर वॉच ने कहा, "एशियाई और वैश्विक संदर्भ में भारत-लैटिन अमरीका संबंधों की फिर से जांच करना। https://asiapowerwatch.com/re-examining-india-latin-america-ties-in-an-asian-and-global- context/, 16 अक्तूबर 2022 को

अभिगम्य।

सप्रू
हाउस
पेपर

सप्रू हाउस पेपर

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली- 110 001, भारत टेलीफोन:
+91-11-23317242, फैक्स: +91-11-23322710

www.icwa.in